साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 29 जून से 05 जुलाई 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08 में...
जनता की लड़ाई आक्रामक तरीके से लड़ें : भूपेश

पेज 12 में...
वातानुकूलित होती पुलिस

वर्ष : 02 अंक : 17 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 03 सूडान युद्ध से जुड़ा छत्तीसगढ़ का नाम

बिन पानी सब सून...

मॉनसून की बेवफाई से सहमे अन्नदाता

प्रदेशभर में महज 10 से 15 फ़ीसदी ही बुआई

अलनिनों और कमजोर मॉनसून से खेती, किसानी और उत्पादन पिछड़ने का खतरा

कमलेश गोगिया/प्रदीप चंद्रवंशी

जून का अंतिम हफ्ता बीत रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के खेत अभी भी सावन की झड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मानसून की सुस्ती और अलनीनो की मार ने प्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालात ऐसे हैं कि राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद और कोरबा समेत कई जिलों में बोनी का रकबा बुरी तरह पिछड़ गया है। कहीं धूल उड़ती सूखी मिट्टी में बीज दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं पानी के अभाव में अंकुरित फसलें खेतों में ही झुलस रही हैं। रूठे मेघों के बीच अब किसान और कृषि वैज्ञानिक दोनों ही फसलों को बचाने के लिए नए विकल्पों की ओर देखने को मजबूर हैं।

बिलासपुर: अब तक केवल 5 हजार हेक्टेयर में बुआई

मानसून सक्रिय होने में विलंब होने और औसत से कम बारिश होने के कारण धान की बोनी पिछड़ गई है। किसान सूखे खेतों में ट्रैक्टर से जोताई तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन सूखी होने के कारण बोनी नहीं कर पा रहे हैं। जून से अब तक जिले में केवल 5 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले 10 वर्षों के औसत के हिसाब से जून माह में 150 मिमी बारिश होती है। नतीजा यह है कि जिले में अब तक सिर्फ 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही धान की बोनी हो सकी है, जबकि सामान्य स्थिति में जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक जिले के कुल रकबे 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर में से 35 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की बुवाई हुई है।

कबीरधाम: दलहन-तिलहन की ओर बढ़ रहे किसान

कबीरधाम जिले में खरीफ सीजन की खेती प्रभावित होने लगी है। बारिश में करीब 15 दिन की देरी से धान की बोनी पिछड़ गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट के साथ किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कबीरधाम जिले में लगभग 1 लाख 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा करीब 32 हजार हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। इस वर्ष गन्ने के रकबे में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हालांकि फिलहाल चने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे भी वर्षा नहीं होने पर सिंचाई के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ेगी। बारिश में देरी के कारण मूंग, उड़द, मक्का और ज्वार जैसी खरीफ फसलों की बुआई में प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन में कमी आने की पूरी आशंका है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों की बजाय अधिक से अधिक गोबर खाद के उपयोग की सलाह दी जा रही है, ताकि मिट्टी की नमी ओर उर्वरता बनी रहे।

धान का कटोरा प्यास की राजधानी

कॉलम - खुरचन
द्वारा- हरिदास

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब लगता है कि इस कटोरे में धान तो बचा है, लेकिन पानी किसी ने चम्मच से खुरचकर निकाल लिया है। राजधानी रायपुर की हालत देखकर लगता है कि हमने शहर को स्मार्ट बनाने की इतनी जल्दी दिखाई कि पानी को बताना ही भूल गई कि उसे भी यहीं रहना है।

जून बीत गया। बादल आए भी, लेकिन शायद उन्होंने रायपुर का नक्शा देख लिया। सोचा- "भाई यहाँ तो तालाबों की जगह कॉलोनियां, खेतों की जगह कांक्रीट और पेड़ों की जगह टावर खड़े हैं, यहां हम बरसकर क्या करेंगे? पानी जमीन में जाएगा कहां? सीधा नाली में जाएगा और सड़कें लबालब हो जाएंगी, फिर वह पानी भाषणों में वापस आ जाएगा।" एक समय था जब बोर कराने पर चार सौ फीट पर पानी मिल जाता था। अब हजार फीट तक ड्रिल करनी पड़ती है। लगता है पानी नहीं, कोई सरकारी फाइल खोजी जा रही हो, जो हर मंजिल पर लिखती हो—"अगले अधिकारी के पास भेजी गई है।"

हमारी धरती भी बड़ी सहनशील माँ है। वर्षों तक उसने अपनी कोख से पानी दिया। हमने बदले में उसकी छाती में हजारों बोरवेल गाड़ दिए। अब जब वह चुप हो गई है तो हम उसे दोषी ठहरा रहे हैं। इंसान का यह पुराना स्वभाव है—जिसे सबसे ज्यादा लूटो, शिकायत भी उसी से करो।

मजेदार बात तो यह भी है कि जल संरक्षण पर सेमिनार पांच सितारा होटलों में होते हैं। मंच पर बैठे विद्वान मिनरल वाटर की बोतल से गला तर करते हुए बताते हैं कि "एक-एक बूंद बचाइए।" बाहर उसी समय टैंकर से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा होता है। यह दृश्य देखकर पानी भी सोचता होगा—"मुझे बचाने वाले ही मुझे बहा रहे हैं।"

शहर का विस्तार देखकर तो भूगोल भी शर्मिंदा है। जो गांव कल तक शहर से बाहर थे, आज शहर के भीतर हैं। जहां कभी धान की बालियां हवा से बातें करती थीं, वहां अब बिल्डरों के होर्डिंग मुस्कुराते हैं— "बुक कीजिए अपना ड्रीम होम।" बस यह नहीं लिखा होता कि "पानी अपने जोखिम पर तलाशें।" उधर गांव की औरतें दो बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर चलती हैं। इधर शहर में कार पर धूल की एक परत जम जाए तो पचास लीटर पानी बहा दिया जाता है। एक तरफ प्यास पैदल चलती है, दूसरी तरफ पानी पाइप से भागता है। यही विकास का नया समाजशास्त्र है।

आज बच्चे किताब में पढ़ते हैं कि "जल ही जीवन है।" कल शायद उन्हें पढ़ाना पड़े—"जल कभी जीवन हुआ करता था।" वे हमसे पूछेंगे—"जब पानी खत्म हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे?" हम गर्व से कहेंगे—"हम वाटर पार्क बना रहे थे, फव्वारे लगा रहे थे और हर नई कॉलोनी के साथ एक नया बोरवेल खोद रहे थे।"

प्रकृति बड़ी ईमानदार लेखाकार है। वह रिश्वत नहीं लेती, केवल हिसाब रखती है। हमने तालाब पाटे, नाले घेर लिए, पेड़ काट दिए और बारिश को नालियों में बहा दिया। अब वह ब्याज समेत अपना हिसाब वसूल रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब रायपुर में मकान का विज्ञापन होगा—"तीन बेडरूम, दो बाथरूम और सप्ताह में तीन दिन पानी। जल्दी करें, सीमित स्टॉक!" तब लोग मकान की लोकेशन नहीं, पानी की उपलब्धता पूछेंगे। इतना ही नहीं, अब तो शादी तय करते समय भी पानी की उपलब्धता पर सवाल पूछे जाने लगे हैं। कुछ दिनों पहले पड़ोस में लड़की वाले पहुँचे। हमसे लड़के वालों की जानकारी लेने लगे। पूछने लगे—हरिदास लड़का क्या करता है? हमने जवाब दिया—इंजीनियर है। फिर दूसरा सवाल पूछा—अच्छा ये बताओ उनके घर में पानी आता है या टैंकर? हम हैरत में पड़ गये। बताया उन्हें- नल तो लगा है, लेकिन गर्मी के दिनों में कभी-कभार टैंकर से काम चलाना पड़ता है। चिंता की बात नहीं, घर के नौकर-चाकर ही टैंकर तक पानी लेने जाते हैं। अब सोचिये भला, असली हैसियत अब नौकरी नहीं, नल तय करने लगा है!

अवसर अभी भी है और हम न सुधरे तो भावी पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। वे कहेंगी—"तुम्हें धान का कटोरा विरासत में मिला था। तुमने हमें प्यास का कटोरा सौंप दिया।" और उस दिन हमारे सारे विकास मॉडल, सारे उद्घाटन, सारे भाषण एक खाली बाल्टी में गूंजती आवाज़ की तरह सुनाई देंगे। धान का कटोरा बचाना है तो भाषणों से नहीं, तालाबों से; नारों से नहीं, वर्षा जल-संचयन से; और विकास की अंधी दौड़ से नहीं, प्रकृति के साथ समझौते से। वरना इतिहास लिखेगा—छत्तीसगढ़ में पानी नहीं सूखा था, इंसान की समझ सूख गई थी।

कांकेर: कम बारिश ने खरीफ फसल की रफ्तार की धीमी

अलनीनो के प्रभाव और जून के अंतिम सप्ताह तक सामान्य से कम बारिश ने कांकेर जिले में खरीफ सीजन की रफ्तार धीमी कर दी है। कांकेर जिले के मैदानी इलाकों में जहां कुछ हद तक बुआई हुई है, वहीं अंतागढ़, कोयलीबेड़ा और दुर्गुकोंदल जैसे आदिवासी विकासखंडों में बारिश की कमी के किसान खेत अभी भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो बुआई और रोपाई दोनों प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर इस वर्ष धान उत्पादन पर पड़ सकता है। बारिश की कमी और देरी को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को कम अवधि वाली धान की किस्मों के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने की सलाह दे रहा है। हालत को देखते हुए एमटीयू-1010, आईआर-64 और एमटीयू-156 जैसी जल्दी पकने वाली किस्मों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कृषि विभाग कांकेर के सहायक संचालक जितेंद्र कोमरा के अनुसार यदि आगामी दिनों में अच्छी वर्षा नहीं हुई तो बुआई और रोपाई दोनों पर व्यापक असर पड़ेगा, जिससे जिले का कुल धान उत्पादन घट सकता है।

धमतरी: बोनी के बाद सूखे पड़े हैं खेत

बारिश की बेरुखी से खेती किसानी पिछड़ गई है। किसान खेतों में धान छिड़ककर अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश बूंदाबांदी से आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को बीज के खराब होने का डर सता रहा है। उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। अलनीनो के असर से धमतरी जिले में सूखा पड़ा हुआ है। मानसून तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। उधर खरीफ की बोनी का समय निकलता जा रहा है। किसान कामता सेन, मुरारजी साहू, चंद्रहास साहू ने बताया कि धान की बोनी के लिए आदर्श समय 1 से 20 जून तक है। वे खेतों में धान की बोनी तो कर चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से बीज के खराब होने की आशंका बनी हुई है। जिन्हीं बारिश नहीं हो रही है, उतने में बीज अंकुरित नहीं होंगे, बल्कि बहुत से बीज की अंकुरण क्षमता प्रभावित होगी। रबी सीजन में अधिकांश किसानों ने चने की खेती की थी। ऐसे में खेत एकदम सूख चुके हैं। बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं। जो किसान रोपा पद्धति से बोनी की तैयारी में हैं, उन्होंने नर्सरी तैयार कर ली है। अब रोपाई के लिए खेत तैयार करने में जुट गए हैं। विडंबना यह है कि दिन रात मोटर पंप चलने के बाद भी खेतों में पानी नहीं चल रहा है। किसान गिरधर साहू, बिसरू साहू ने बताया कि जब तक बारिश नहीं होगी, खेतों में पानी ठहर पाना मुश्किल है।

रायगढ़: बोनी के बाद सूख गए 40 फीसदी अंकुरण

रायगढ़। जिले के किसानों ने रोपा के बजाय खेतों में बोनी तो 20 दिन पहले कर दी थी लेकिन बारिश नहीं होने से अंकुरण 40 फीसदी अब सूख चुके हैं। हालात यह है कि अब खेतों में किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। बारिश नहीं होने से करीब 20 दिन खेती का काम पिछड़ चुका है। इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा।

राजनांदगांव: जिले में 10% भी बुआई नहीं खेती पिछड़ी उत्पादन में होगी कमी

अलनीनो के प्रभाव के चलते बारिश की बेरुखी बनी हुई है, जिससे खेती किसानी का कार्य प्रभावित हो गया है। लगभग 10-15 दिनों में भी जिलेभर में 10 प्रतिशत किसानों ने धान की बुआई नहीं की है। जिससे खेती का कार्य पिछड़ा हुआ है। देर से बुआई और मौसम की बेरुखी के चलते इसका सीधा प्रभाव फसलों पर पड़ेगा, जिससे उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। स्थिति यह है कि बारिश के इंतजार में कई किसान अब तक अपने खेतों की जुताई भी नहीं कर पाए हैं और जिन किसानों ने खेतों में धान के बीज बोए हैं उन्हें अब फसल अंकुरित नहीं होने की चिंता सता रही है। मानसून सक्रिय नहीं होने को लेकर कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. गुंजन झा ने बताया कि अलनीनो एक वैश्विक जलवायु घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग के समुद्री जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है।

गरियाबंद: अलनीनो के असर से सूखे जैसे हालात

जून का अंतिम सप्ताह समाप्त होने को है लेकिन अब तक जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। कई स्थानों पर खेतों की मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी है कि वे चट्टान जैसी दिखाई दे रही है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम की बेरुखी देख किसान निजी बोरवेल से सिंचाई कर फसल बुआई कर रहे हैं वहीं सिंचाई के मुख्य साधन नहर नाली सूखे पड़े हैं।

दुर्ग: किसानों ने किया दलहन तिलहन फसल की ओर रुख

अलनीनो के संभावित खतरे को देखते हुए दुर्ग जिले के किसानों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व दुर्ग जिला कृषि विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। यहां के किसान धान खेती की निर्भरता के बजाय अरहर, मूंग एवं उड़द तथा तिलहनी फसल जैसे तिल और सोयाबीन फसलों की ओर रुख करने लगे हैं। दुर्ग जिले में 1.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की फसल ली जाती है। 1 लाख 86 हजार किसान हैं। इनमें से 25 प्रतिशत किसान यानी 46 हजार किसान दलहनी व अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके लिए जिला बीज भंडार से बीजों की खरीदी कर चुके हैं। कृषि विशेषज्ञ के हिसाब से धान लगाने के बजाय कम पानी में होने वाली दलहनी फसल कम पानी में तैयार होती है। रोपा विधि के बदले सीधी बुआई अपनाएं इससे 20 प्रतिशत पानी की बचत होगी एवं साथ ही लगभग 5000 रुपए प्रति एकड़ लागत में भी कमी आएगी। फसल 12 से 15 दिन पहले पकेगी।

कोरबा : मानसून की बेरुखी, जिले में 22 सौ हेक्टेयर घटा बोनी का रकबा

मानसून की बेरुखी का असर अब खेतों में दिखने लगा है। जून का महीना बीतने को है, बारिश न होने की स्थिति को देखते हुए आंशिक सूखे की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष बोनी का रकबा 22 सौ हेक्टेयर कम कर दिया है। जून महीने तक बीते वर्ष बोनी रकबा 10 हजार हेक्टेयर पहुंच चुका था। इस वर्ष बोनी रकबा 7 हजार 200 के लगभग हुआ है।

जांजगीर : मानसून की राह तक रहे किसान

जून का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन अब तक जिले में मानसून की जोरदार बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, पर धान की बुआई शुरू करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया है। हालांकि जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 5 जुलाई से नहर की धार छूटेगी, इसके बाद कृषि कार्यों में तेजी आएगी।

सरगुजा : मानसून ने बढ़ाई किसानों की चिंता, सूख रहे बीजों के अंकुर

मानसून की बेरुखी ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। प्री-मानसून की बारिश के बाद खरीफ फसलों के लिए किसानों ने अपने खेतों को तैयार कर लिया है लेकिन बारिश के अभाव में न तो बुवाई कर पा रहे हैं न ही अभी तक धान का बीड़ा ही लगा पाए हैं। अवर्षा की स्थिति को देखते हुए विकासखण्ड मैनपाट, सीतापुर, बतौली और लुण्ड्रा में बड़ी संख्या में किसानों ने बीड़ा तैयार न कर सीधे अपने खेतों में धान के बीजों की सूखी बुआई कर दी है लेकिन लिलिबाणी धूप विकासखण्ड खेतों की नमी सूख जाने के कारण धान के अंकुर झुलस जा रहे हैं। किसानों ने मक्का सहित अन्य फसलों की ओर रुख कर दिया है, कुछ ने धान का थरहा भी लगाया है लेकिन खेतों में दरार पड़ने के कारण फसल तेजी से झुलस रही है। मौसम विज्ञानी 2-3 दिन बाद अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने एवं मानसून के अग्रसर होने के साथ ही बारिश होने की संभावना जता रहे हैं।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

- कम अवधि वाली धान किस्में अपनाएं।
- रोपा की जगह सीधी बुआई करें।
- दलहन-तिलहन और मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें लें।
- नमी संरक्षण पर ध्यान दें, फसल बीमा का लाभ उठाएं।

सूडान युद्ध से जुड़ा छत्तीसगढ़ का नाम

रायपुर की SBL एनर्जी पर विस्फोटक सप्लाई का आरोप, अमेरिका ने किया बैन

रायपुर। अमेरिका ने सूडान में चल रहे गृहयुद्ध से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने राजधानी रायपुर की SBL एनर्जी लिमिटेड कंपनी के सीईओ आलोक चौधरी समेत कुल 8 व्यक्तियों और संस्थाओं को बैन किया है। अमेरिकी वित्त विभाग (यूएस ट्रेजरी) का आरोप है कि, रायपुर की एसबीएल एनर्जी ने सूडान के सैन्य नेटवर्क से जुड़ी संस्था टारगेट मल्टी एक्टिविटीज कंपनी (TMAC) को विस्फोटक और उससे संबंधित सामग्री की आपूर्ति की। विभाग के अनुसार इन सामग्रियों का इस्तेमाल सूडान में जारी संघर्ष के दौरान किया गया। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक एसबीएल एनर्जी कंपनी ने साल 2024 से अब तक TMAC को विस्फोटक और संबंधित सामग्री की 200 से अधिक खेप भेजी हैं। विभाग का दावा है कि यह सामग्री ऐसे नेटवर्क तक पहुंची, जो सूडान में चल रहे गृहयुद्ध को समर्थन दे रहे हैं। सूडान में गृह युद्ध 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। यह देश की नियमित सेना सूडानी आर्म्ड फोर्सेज (SAF) और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच चल रहा है। दोनों पक्ष पहले सहयोगी थे, लेकिन सेना में RSF के विलय, सत्ता पर नियंत्रण और देश के नेतृत्व को लेकर विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। यह लड़ाई धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। संयुक्त राष्ट्र इसे दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक मानता है। युद्ध अभी भी जारी है।

कंपनी ने अमेरिकी आरोपों को बताया गलत

दरअसल, एसबीएल एनर्जी (पहले नाम अमीन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड) डायनामाइट और TNT जैसे विस्फोटकों की सप्लाई करती है। अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। सीईओ आलोक चौधरी ने कहा कि उनकी कंपनी किसी भी तरह के रक्षा उत्पाद या सेना में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक नहीं बनाती। कंपनी ने बताया कि वह भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक विस्फोटक बनाती है। इनका उपयोग खनन, सड़क और पुल जैसी निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है।

2022 से अब तक सिर्फ 10 खेप भेजने का दावा

कंपनी के CEO ने अमेरिकी ट्रेजरी के आरोपों को गलत बताया। कंपनी का कहना है कि साल 2024 में 200 से ज्यादा खेप नहीं भेजी गईं। साल 2022 से अब तक सिर्फ 10 खेप में औद्योगिक विस्फोटकों की आपूर्ति की गई है।

प्रतिबंध का क्या होगा असर

अमेरिका के प्रतिबंध लागू होने के बाद एसबीएल एनर्जी और उसके सीईओ आलोक चौधरी की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। इसके अलावा कोई भी अमेरिकी नागरिक, कंपनी या वित्तीय संस्था उनके साथ व्यापारिक या वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेगी। हालांकि, इस कार्रवाई का भारत में कंपनी के संचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है।

इन 8 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के OFAC ने कुल 8 लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनके नाम हैं:

- आलोक चौधरी - CEO, SBL Energy Limited (भारत)
- SBL Energy Limited - रायपुर, छत्तीसगढ़ की विस्फोटक निर्माण कंपनी
- Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC) - सूडान
- Ports Engineering Company Ltd. - सूडान
- तारिक हुसैन मुहम्मद मदानी - सूडानी नागरिक
- एनरिक डेनियल पलासियोस क्विंटानिला - पनामा
- जैक पीटर डर्मन गुज़मान - पनामा
- फ्रेडी अलेजांद्रो लोपेज़ ओकाम्पो - कोलंबिया

चलती स्लीपर बस में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। धमतरी से रायपुर आ रही महेंद्र ट्रेवल्स की स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हालांकि चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को तत्काल बस से नीचे उतार लिया गया, जिससे जनहानि टल गई। जानकारी के अनुसार, घटना जगदलपुर नेशनल हाईवे पर अभनपुर के पास हुई। धमतरी से रायपुर की ओर आ रही महेंद्र ट्रेवल्स की स्लीपर बस में अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। बस में आग लगते ही चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोक दिया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही देर में आग ने बस के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। आग लगने से बस को काफी नुकसान पहुंचा है।

सूने मकानों और वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली। राजधानी रायपुर में सूने मकानों और दोपहिया वाहनों को निशाना बनाने वाले गिरोह के दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही शहर में हुई चोरी और नकबजनी के आठ मामलों का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवर, वारदात में इस्तेमाल की गई दो एक्टिवा समेत करीब 4.50 लाख रुपये का सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की दोपहिया गाड़ियों से शहर की अलग-अलग कॉलोनियों में घूमते थे। सूने मकानों की रेकी करने के बाद मौका मिलते ही नकबजनी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह ने डीडी नगर थाना क्षेत्र में पांच सूने मकानों में चोरी की, जबकि डीडी नगर और राखी थाना क्षेत्र से तीन दोपहिया वाहन भी चुराए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही गिरोह के एक सदस्य सिद्धार्थ सिंह उर्फ सिद्धू को गिरफ्तार कर चुकी थी। उससे पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर फरार चल रहे आशुतोष सिंह उर्फ सूरज और साहिल सोनकर की पहचान हुई।

30 जून से इंजीनियरिंग कॉलेजों की काउंसिलिंग शुरू

रायपुर। राज्य में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी टेक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की काउंसिलिंग 30 जून से शुरू हो रही है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने काउंसिलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्रवेश तीन चरणों की काउंसिलिंग के बाद होगा। काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण के लिए अभ्यर्थियों को अलग-अलग से आवेदन करना होगा। राज्य में 34 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 11 हजार 514 सीटें है। प्रथम चरण की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 30 जून से 6 जुलाई तक चलेगी। जिसके बाद मेरिट सूची 7 जुलाई को जारी की जाएगी। जिसपर दावा आपत्ति 8 जुलाई तक कर सकेंगे। आवंटन व रिजल्ट 10 जुलाई को जारी होंगे, जिसमें प्रवेश विद्यार्थियों को 11 जुलाई से 15 जुलाई तक लेना होगा। ऐसे ही द्वितीय चरण की प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन 17 से 21 जुलाई तक चलेगी। मेरिट सूची 22 जुलाई को जारी होगी जिस पर दावा-आपत्ति 23 जुलाई तक कर सकेंगे; उसके बाद आवंटन व रिजल्ट 25 जुलाई को जारी होगी।

रायपुर निगम की विशेष सामान्य सभा 6 जुलाई को

जलसंकट, सफाई और अवैध प्लॉटिंग पर होगी चर्चा

रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही जलापूर्ति, सफाई और अवैध निर्माण संबंधी समस्याओं के बीच नगर निगम ने विशेष सामान्य सभा बुलाने का निर्णय लिया है। महापौर मीनल चौबे के पत्र पर सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने 6 जुलाई को विशेष सामान्य सभा की तिथि निर्धारित की है। बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों जैसे जलसंकट, सफाई व्यवस्था, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। निगम एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विशेष सामान्य सभा 15 दिनों के भीतर बुलाई जा सकती है। 22 जून को अधिसूचना जारी होने के बाद अब इस बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम के अनुसार शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। वर्तमान में कई क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं सफाई व्यवस्था और अवैध निर्माण के मामलों को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष ने इस बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मार्च में हुई बजट सामान्य सभा में इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन अब बारिश के मौसम में जलसंकट पर विशेष बैठक बुलाना प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े करता है। हालांकि निगम प्रशासन का कहना है कि बैठक में सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

इंस्टाग्राम पर डॉक्टर बनकर युवती से 3.23 लाख ठगे

रायपुर। राजधानी रायपुर में साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर खुद को डॉक्टर बताकर 28 साल की महिला से दोस्ती की और विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देकर 3.23 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर महिला का भरोसा जीता। इसके बाद विदेश से गिफ्ट भेजने की बात कहकर एयरपोर्ट चार्ज, कस्टम ड्यूटी, टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर अलग-अलग किश्तों में 3.23 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, कुशालपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर के पास रहने वाली 28 वर्षीय युवती की करीब दो वर्ष पहले drkhan666 नाम की इंस्टाग्राम आईडी के जरिए एक व्यक्ति से पहचान हुई थी। खुद को डॉक्टर बताने वाले आरोपी ने पहले युवती से दोस्ती की और लगातार चैटिंग कर उसका भरोसा जीत लिया। बाद में उसने युवती का मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सऐप पर बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती से उसकी तस्वीरें और वीडियो भी मंगवाए। खुद को विदेश में कार्यरत डॉक्टर बताया। कुछ समय बाद आरोपी ने महिला से कहा कि उसने विदेश से उसके लिए महंगे गिफ्ट भेजे हैं। इसके बाद उसने गिफ्ट की डिलीवरी के बहाने महिला से उसके घर का पता भी ले लिया।

केंद्र ने जारी किए RTE के 339.73 करोड़

4 साल से रुका हुआ था पैसा, राज्य के 3.70 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा

रायपुर। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी स्कूलों की फीस के भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 339.73 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह पैसा पिछले चार साल से लंबित था। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि पहली बार केंद्र सरकार ने आरटीई के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम भेजी है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन बच्चों की फीस सरकार देती है। इसमें 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार अपने हिस्से का भुगतान समय पर करती रही, लेकिन केंद्र से पैसा आने में लगातार देरी हो रही थी। अब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल के बाद केंद्र ने यह लंबित राशि जारी कर दी है।

पैसा शिक्षा विभाग को मिल चुका है

समग्र शिक्षा की आयुक्त किरण कौशल ने बताया कि केंद्र से मिले 339.73 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीई के लिए पहली बार इतनी बड़ी राशि एक साथ मिली है। इसके अलावा पीएबी के तहत भी कई योजनाओं को मंजूरी मिली है।

दूसरे राउंड की एडमिशन प्रक्रिया जारी

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के दूसरे राउंड की एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। इस साल से सिर्फ कक्षा-1 में ही एडमिशन दिए जा रहे हैं। राज्य के निजी स्कूलों में कक्षा-1 की 21,975 सीटें आरटीई के तहत आरक्षित हैं। पहले राउंड में 13,383 बच्चों को एडमिशन मिला। बची हुई सीटों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले राउंड में 369 ऐसे निजी स्कूल रहे, जहां एक भी आवेदन नहीं आया।

साप्ताहिक शहर सत्ता

डायल 112 होगा एकमात्र इमरजेंसी नंबर

100, 101, 102, 108, 1033 जैसे नंबर होंगे बंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित देश में जल्द ही सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर एकीकृत होकर सिर्फ डायल-112 के जरिए संचालित होंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने में डायल-100, 101, 102, 108, 1033, 1091 समेत सभी आपातकालीन नंबरों को 112 में मर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्यों से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में कवायद तेज हो गई है। हाल ही में गृह विभाग के अधिकारियों ने डायल-112 में इमरजेंसी कॉल को एकीकृत करने पर बैठक की। इसके लिए विस्तृत एक्शन प्लान बन रहा है। प्रदेश में फिलहाल डायल-112 की करीब 400 और मेडिकल इमरजेंसी 108 की करीब 375 गाड़ियां संचालित हैं। पुलिस, फायर और मेडिकल सहायता के लिए पहले से डायल-112 से कॉल दर्ज किए जाते हैं। हालांकि अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर होने और लोगों में जागरुकता की कमी के कारण भ्रम की स्थिति बनती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य सभी सेवाओं को पूरी तरह एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रतिक्रिया समय कम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज और आपात सहायता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 को सेव लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में यह ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता न मिलना कई बार मौत का कारण बनता है। इसलिए ट्रॉमा केयर तक त्वरित पहुंच संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। 2018 से संचालित है डायल-112 छत्तीसगढ़ में डायल-112 की शुरुआत 15 अगस्त 2018 को "एक्के नंबर, सब्बो बर" थीम के साथ हुई थी। शुरुआत में यह सेवा सीमित जिलों तक थी। बाद में 18 मई को इसे प्रदेश के सभी 33 जिलों में विस्तार दिया गया। इसके साथ 400 नई डायल-112 गाड़ियां और एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की गई।

छत्तीसगढ़ में ऐसे काम करता है सिस्टम

राज्य में किसी भी आपात स्थिति में डायल-112 पर कॉल आने के बाद कॉल सेंटर लोकेशन और घटना की जानकारी दर्ज करता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर यह सूचना 108 एंबुलेंस सेवा को भेजी जाती है, जबकि आग लगने की सूचना अलग से फायर विभाग को भेजी जाती है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सूचना और लोकेशन ट्रांसफर होने में लगने वाले समय को खत्म करने के लिए अब सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है।

रोज करीब 10 हजार कॉल संभाल रहा डायल-112

कुल अटेंड कॉल: 3,06,264

कुल रजिस्टर्ड इवेंट: 79,782

ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ में नई दिल्ली के कलाकार करेंगे रामलीला

अंबिकापुर। सरगुजा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस 29 एवं 30 जून को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव में जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, कलाकार, पर्यटक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल होंगे। महोत्सव की खास बात यह है कि इस बार नई दिल्ली के कलाकार रामलीला की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव का शुभारंभ 29 जून को सुबह 10:30 बजे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में होगा। दिनभर छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति पर आधारित लोकनृत्य, लोकगीत एवं पारंपरिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। शाम को प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक एवं सांस्कृतिक कलाकार अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से महोत्सव की गरिमा बढ़ाएंगे।

नींद में नानी-नातिन को सांप ने डसा, मौत

अंबिकापुर। बारिश का सीजन शुरु होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटागहना में शनिवार की रात को जमीन में सोए नानी-नातिन को सांप ने डस लिया। परिजन बच्ची को इलाज के लिए राजपुर स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। यहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। अंबिकापुर लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जबकि नानी की घर में ही मौत हो गई। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नरकालो निवासी वृद्ध महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। महिला भी अपनी बेटी और उनके बच्चों के साथ जमीन में सोई थी। बलरामपुर जिले के ग्राम घोरघड़ी के फुफंदीपारा निवासी 8 वर्षीय करिश्मा शुक्रवार को अपनी नाना-नानी के घर ग्राम कोटागहना घूमने आई थी। शनिवार की रात वह अपनी नानी नंदी (56 वर्ष) पति सोला के साथ जमीन पर सो रही थी। रात लगभग 11 बजे सांप ने पहले करिश्मा को डस लिया। कुछ काटने से वह रोने लगी। इस दौरान नानी की नींद खुल गई, उसने देखा तो करिश्मा के पास सांप था।

सोनेसिली पंचायत की 126 एकड़ सरकारी जमीन कब्जामुक्त!

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोनेसिली ने सरकारी भूमि संरक्षण और ग्रामीण विकास की दिशा में मिसाल पेश की है। पंचायत और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से करीब 126 एकड़ शासकीय भूमि को बेजा कब्जे से मुक्त कराया गया है। वर्षों से अतिक्रमण और विवादों में रही यह जमीन अब पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण सुविधाओं के विकास के लिए उपयोग होगी। इस भूमि पर जंगल, तालाब, खेल मैदान और अन्य जनहित कार्यों की योजना तैयार की गई है। पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार 40 एकड़ भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए सौंपी गई है। इस जमीन पर बड़े स्तर पर पौधरोपण कर हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे गांव में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में यह क्षेत्र हरियाली से भर जाएगा। जल संकट और भूजल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 14 एकड़ भूमि पर तालाब निर्माण की योजना बनाई गई है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के साथ इसका लाभ ग्रामीणों और किसानों को मिलेगा। पंचायत का उद्देश्य जल संसाधनों को मजबूत करना है। गांव के युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 एकड़ भूमि खेल मैदान के लिए आरक्षित की गई है।

लिवइन-कपल के बच्चों को मिलेगी संपत्ति

- **यूसीसी के तहत छत्तीसगढ़ में लागू करने हो रही स्टडी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) लागू करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। राज्य सरकार की उच्चस्तरीय समिति अब गोवा और उत्तराखंड में लागू UCC मॉडल की स्टडी करेगी। साथ ही गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में UCC के लिए गठित समितियों के अनुभवों और सुझावों का भी एनालिसिस किया जाएगा। गोवा और उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हैं।

इनमें लिव-इन कपल के बच्चों को संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। इन्हीं सभी पहलुओं के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए UCC का मसौदा तैयार किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति में रिटायर्ड IAS शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं। वहीं इस लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, UCC हिंदुस्तान के लिए पेचीदा विषय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे और परपंच कर रही है।

आदिवासी समुदायों को मिल सकती है विशेष छूट

जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 30.62 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की है। संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराओं और प्रथागत कानूनों को विशेष संरक्षण प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से आंशिक या पूर्ण छूट देने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। उच्चस्तरीय समिति इस बात की स्टडी करेगी कि आदिवासी समुदायों के प्रथागत कानूनों, रीति-रिवाजों और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है।

हिंदू समुदाय को लेकर शादी के नियम

गोवा के लोग एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती या 30 साल की उम्र तक वह बेटे को जन्म नहीं दे पाती, तो ऐसी स्थिति में हिंदू पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। यह नियम सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए है। हालांकि, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि यह प्रावधान अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। 1910 से इसका फायदा किसी को नहीं दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप संबंधों से जन्मे बच्चों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं।

6 हजार तकनीशियनों को सरकारी लैब बंद हो जाने पर बाबू बनाने का विकल्प

हमर लैब बंद होने के साइड इफेक्ट

रायपुर। राज्य के सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब को निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी के बीच एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सालों से मरीजों के खून-यूरिन की जांच कर रहे करीब 6 हजार मेडिकल लैब तकनीशियनों (एमएलटी) को अब दूसरे विभागों में भेजने की तैयारी है।

दरअसल, निजी हाथों में कमान जाते ही सरकारी तकनीशियनों के पास मूल विभाग में काम नहीं बचेगा। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने तकनीशियनों के प्रतिनिधिमंडल से खुद विकल्प मांगा है कि वे कहां जाना चाहते हैं? बरसों से तकनीकी काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब आयुष्मान योजना और सीजीएमएससी में बाबू बनने, फूड एंड ड्रग विभाग में सैंपल कलेक्टर या पंचायत विभाग में क्लर्क बनने का ऑफर दिया जा रहा है। अचानक आए इस फैसले से 15-20 साल से सेवाएं दे रहे तकनीशियन हैरान हैं और विभाग में खलबली मची हुई है। इन कर्मचारियों का चयन किसी सामान्य भर्ती से नहीं, बल्कि कठिन प्रतियोगी परीक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए हुआ था। पैरामेडिकल कोर्स के बाद इन्होंने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। सालों के इस तकनीकी अनुभव और विशेषज्ञता के बाद अब इन्हें गैर-तकनीकी कामों में धकेले जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों और एमएलटी प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा से इतना स्पष्ट हो गया है कि लैब सेवाओं के निजी हाथों में जाने के साथ बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बदली जाएंगी।

विकल्प को लेकर एमएलटी प्रतिनिधियों से चर्चा

यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकारी पैथोलॉजी का निजीकरण करने जा रही है। शुरुआती चरण में चार जिला अस्पतालों में संचालित 'हमर लैब' को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले चरणों में बाकी जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी की लैब भी इस दायरे में आएंगी। हालांकि, अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अफसरों और एमएलटी प्रतिनिधियों की चर्चा से साफ है कि लैब सेवाओं के निजी हाथों में जाते ही तकनीकी स्टाफ का सेटअप पूरी तरह बदल जाएगा।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

फिर उलझ गया दस्तावेजों का सिस्टम

विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने, रोजगार पाने या फिर भ्रमण का सपना संजोने वाले लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने पासपोर्ट के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके तहत अब 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपए की जगह 2,500 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि तत्काल सेवा के लिए 3,500 रुपए के बजाय 5,000 रुपए देने होंगे।

सरकार की ओर से शुल्क बढ़ोतरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इसका असर निश्चित रूप से उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ेगा, जिनके बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर मिलते हैं। साथ ही उन श्रमिकों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो विदेश में रोजगार के जरिए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। इसी के साथ पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न मानने को लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। सड़कों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह सवाल उठने लगा है कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय विद्यार्थियों का विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने में खासा रुझान देखा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में 12 लाख से अधिक भारतीय विद्यार्थी विभिन्न देशों में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, लेकिन अब इन छात्रों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। विदेशी शिक्षा संस्थानों में बढ़ती फीस और वीजा नियमों में की जा रही सख्ती से देश के छात्रों के कदम ठिठक रहे हैं। ऐसे में पासपोर्ट के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी उनके इरादों को और कमजोर कर सकती है।

इसी तरह विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिक वर्ग पर भी इसका विपरीत असर पड़ने की आशंका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में करीब साढ़े तीन लाख भारतीय श्रमिक विदेश गए थे। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आर्थिक स्थिति के आधार पर पासपोर्ट आवेदन शुल्क में रियायत नहीं दी जा सकती है। सरकार का मकसद केवल राजस्व अर्जित करना ही नहीं, बल्कि आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना भी होना चाहिए। यही नहीं, पासपोर्ट के नागरिकता का प्रमाण न होने को लेकर एक नई बहस भी छिड़ गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र अगर नागरिकता को साबित नहीं करते, तो फिर इसके लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है। यह विचित्र बात है कि एक तरफ सरकार का दावा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और यह कभी भी नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए पात्रता साबित करने हेतु जिन 12 वैध दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें पासपोर्ट भी शामिल है।

यह बात भी सामने आती है कि देश भर में हो रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की ओर से नागरिकता की आंशिक रूप से जांच की जा रही है। ऐसे में अब यह मांग भी उठ रही है कि सरकार को कानूनी ढांचे में संशोधन कर पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को भारतीय नागरिकता का वैध और निर्णायक प्रमाण घोषित करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भी कई देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार साफ कहा कि पासपोर्ट केवल यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का प्रमाण। अधिकारियों ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, लेकिन यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है।

जाम के साथ माइक्रोप्लास्टिक का चखना बिल्कुल मुफ्त !

डॉ. चंद्र त्रिखा

हमारे शहरों में बढ़ती जनसंख्या और उसके अनुरूप अनियोजित भवन निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से जानलेवा साबित हो रहे हैं। आवासीय इलाकों में बिना सोचे-समझे व्यावसायिक गतिविधियां और कारखाने खोल दिए जाते हैं। ऐसे में जब कभी आग लगती है तो संकरी गलियों के कारण दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं। ऐसे में हादसा अनगिनत जानों को लील लेता है। प्रशासन द्वारा निर्धारित भवन निर्माण के नियम कोई रुकावट नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए बेहद जरूरी सुरक्षा कवच हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अवैध निर्माण लालची बिल्डरों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ से फलते-फूलते हैं। बिल्डर सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करते हैं, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और खरीदार अंत में फंसता है। छोटे शहरों में स्थिति और भी बदतर है। यहां नगर पालिकाएं संसाधनों की कमी और स्थानीय दबाव के आगे घुटने टेक देती हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे और सुरक्षित भवन निर्माण की दिशा में तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए तो भविष्य में आगजनी की घटना अथवा आने वाला एक छोटा सा भूकंप भी हमारे विकास के सभी दावों को मलबे में बदल देगा। इन्हीं हालातों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...

विकास की इस तेज भागदौड़ में हम यह बुनियादी बात भूल जाते हैं कि शहर केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे के बेजान ढांचे नहीं हैं; बल्कि ये एक जीती-जागती व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को सही ढंग से चलने और सुरक्षित रहने के लिए एक दूरदर्शी योजना की बहुत जरूरत होती है। आज हमारे शहर बिना किसी सही योजना के जिस तरह से फैल रहे हैं, वह किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी नाकामी 'भवन निर्माण के नियमों' की अनदेखी के रूप में सामने आती है, जो हमारे शहरों को एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल रही है। भवन निर्माण के नियम किसी भी सुनियोजित शहर की रीढ़ होते हैं। ये वे कानूनी और तकनीकी दिशा-निर्देश हैं जो यह पक्का करते हैं कि कोई भी इमारत रहने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो।

शहरों का विकास आधुनिक युग की एक बड़ी और सुखद सच्चाई है। हर दिन हजारों लोग एक बेहतर जिंदगी, रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की आस में गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमक-दमक वाली जीवनशैली शहरों को बहुत आकर्षक बनाती है। लेकिन, विकास की इस तेज भागदौड़ में हम यह बुनियादी बात भूल जाते हैं कि शहर केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे के बेजान ढांचे नहीं हैं; बल्कि ये एक जीती-जागती व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को सही ढंग से चलने और सुरक्षित रहने के लिए एक दूरदर्शी योजना की बहुत जरूरत होती है। आज हमारे शहर बिना किसी सही योजना के जिस तरह से फैल रहे हैं, वह किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी नाकामी 'भवन निर्माण के नियमों' की अनदेखी के रूप में सामने आती है, जो हमारे शहरों को एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल रही है। भवन निर्माण के नियम किसी भी सुनियोजित शहर की रीढ़ होते हैं। ये वे कानूनी और तकनीकी दिशा-निर्देश हैं जो यह पक्का करते हैं कि कोई भी इमारत रहने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। इन नियमों में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। जैसे कि इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली खाली जगह, जमीन के अनुपात में निर्माण की अधिकतम सीमा, आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम, भूकंप सहन की क्षमता, और आपात स्थिति में बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते। इसके पीछे का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि पड़ोसियों को भी पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। जब शहरों का फैलाव बिना किसी पक्की योजना के, रातों-रात मनमाने तरीके से होता है, तो सबसे पहले इन्हीं नियमों की बलि चढ़ाई जाती है। ज्यादा मुनाफे की चाहत और जगह की कमी के नाम पर निर्माण करने वाले ठेकेदार और खुद भवन मालिक भी इन नियमों को ताक पर रख देते हैं। नतीजा यह होता है कि तंग गलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, जिनमें न तो हवा आने का कोई रास्ता होता है और न ही धूप का। इस अनदेखी का सीधा असर उन खौफनाक हादसों के रूप में सामने आता है, जो अब हमारे शहरों की रोजमर्रा की कहानी बन चुके हैं। बहुमंजिला इमारतों में भयानक आग लगने या उनके भरभरा कर गिर जाने की दर्दनाक खबरें अब आम हो गई हैं। हवा के आने-जाने का सही रास्ता न होने के कारण आग लगने पर लोग लपटों से कम, और जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण ज्यादा जान गंवाते हैं। इसी तरह, कमजोर नींव, घटिया निर्माण सामग्री और बिना अनुमति के बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों के कारण कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। जब इमारत बनाने से पहले मिट्टी की जांच और ढांचे की मजबूती परखने जैसे जरूरी कामों को नजरअंदाज किया जाता है, तो भूकंप का एक हल्का झटका या तेज बारिश भी भारी तबाही ला सकती है। बिना योजना के बसाए गए शहर जलभराव जैसी गंभीर मुसीबतों का भी मुख्य कारण हैं। भवन निर्माण नियमों में पानी की निकासी और बारिश के पानी को सहेजने के सख्त नियम होते हैं। अवैध निर्माण की होड़ में प्राकृतिक जल स्रोतों, नालों और तालाबों को मिट्टी से भरकर वहां ईंट-पत्थर के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं।

इसका नतीजा यह होता है कि थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। पानी के निकलने का कोई रास्ता न बचने के कारण इमारतों के निचले हिस्सों में पानी भरने से होने वाली मौतें अब एक डरावनी सच्चाई बन गई हैं। यह सीधे तौर पर नगर नियोजन या शहर बसाने की योजना का मजाक उड़ाने का परिणाम है। यह डरावनी स्थिति एक-दो दिन में पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे ढीली प्रशासनिक व्यवस्था, लापरवाह नगर निगम और लालची जमीन माफियाओं का भ्रष्ट गठजोड़ जिम्मेदार है। दिन के उजाले में खुलेआम अवैध निर्माण होता रहता है और जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी रहती है। रिश्वत और पहुंच के दम पर नियमों के खिलाफ बनी इमारतों को भी निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र आसानी से मिल जाते हैं। सस्ते घर के लालच में लोग ऐसी इमारतों में अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, जो कभी भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। अब वह समय आ गया है कि बिना योजना के बढ़ते शहरीकरण और नियमों की अनदेखी पर गंभीरता से विचार किया जाए। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को अपनी जिम्मेदारी सख्ती से समझनी और निभानी होगी। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जुर्माना लेकर अवैध निर्माण को वैध कर देने की गलत परंपरा को तुरंत बंद करना होगा। हवाई सर्वेक्षण और उपग्रह से प्राप्त चित्रों जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माणों को शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए। घर खरीदते या बनाते समय यह जांचना हर नागरिक का भी फर्ज है कि वह इमारत सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हो। यदि बिना सोचे-समझे हो रहे शहरीकरण पर नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ, तो ये बेतरतीब जंगल इसी तरह दर्दनाक हादसों को न्योता देते रहेंगे।

एक बार एक संत ने अपने दो भक्तों को बुलाया और कहा आप को यहां से पचास कोस जाना है। एक भक्त को एक बोरी खाने के समान से भर कर दी और कहा जो लायक मिले उसे देते जाना। और एक को खाली बोरी दी उससे कहा रास्ते में जो उसे अच्छा मिले उसे बोरी मे भर कर ले जाए। दोनो निकल पड़े जिसके कंधे पर समान था वो धीरे चल पा रहा था। खाली बोरी वाला भक्त आराम से जा रहा था। थोड़ी दूर उसको एक सोने की ईंट मिली उसने उसे बोरी में डाल लिया। थोड़ी दूर चला फिर ईंट मिली उसे भी उठा लिया। जैसे-जैसे चलता गया उसे सोना मिलता गया और वो बोरी में भरता हुआ चल रहा था। और बोरी का वजन बढ़ता गया उसका चलना मुश्किल होता गया और सांस भी चढ़ने लग गई। एक एक कदम आगे चलना कठिन होता गया। दूसरा भक्त जैसे-जैसे चलता गया रास्ते में जो भी मिलता उसको बोरी में से खाने का कुछ समान देता गया धीरे-धीरे बोरी का वजन कम होता गया। और उसका चलना आसान होता गया। जो बांटता गया उसका गंतव्य स्थान तक पहुंचना आसान होता गया। और जो लालच में आकर इकट्ठा करता रहा वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हम सभी को अब ये सोचना चाहिए कि हमने जीवन में क्या बांटा और क्या इकट्ठा किया हम मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। दरअसल लालच ही वह बला है जिससे मनुष्य उबर नहीं पाता और जो इससे उबर जाता है अपनी मंजिल पा लेता है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

रक्षामंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई

विपक्ष ने लगाया आरोप, भाजपा ने किया पलटवार

नई दिल्ली। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. उनका आरोप है कि विपक्ष ने कई महीनों तक झूठ फैलाया, शत्रु देश के प्रचार को बढ़ावा दिया और संसद में रक्षा मंत्री के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार सैनिकों के बलिदान से इनकार कर रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए गए भाषण का एक वीडियो क्लिप साझा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर संसद को गुमराह किया गया. साथ ही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले छह जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में अहम जानकारी छिपाई. अमित मालवीय ने कहा कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. उनके मुताबिक, रक्षा मंत्री का बयान एक विशेष संदर्भ में दिया गया था, जिसका उद्देश्य उस झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार का खंडन करना था जिसमें दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने लड़ाकू पायलट खो दिए थे.उन्होंने कहा कि इस तरह का झूठा प्रचार ऑपरेशन की सफलता को कमजोर करने और देश का मनोबल गिराने के लिए किया जा रहा था. मालवीय ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर रक्षा मंत्री के बयान की एक पंक्ति को संदर्भ से अलग कर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश की.

'ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा'

बीजेपी नेता ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल सैन्य अभियान था. अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी और पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए. इसके अलावा नियंत्रण रेखा (LoC) के पास पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अभियान के दौरान अपनी सटीकता, पेशेवर क्षमता और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन किया. अमित मालवीय ने कहा कि सरकार ने उन सभी जवानों का पूरा सम्मान किया, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए गए हैं, जो उनकी वीरता को हमेशा याद रखने का प्रतीक है।

राहुल गांधी के गुमशुदगी पोस्टर पर कांग्रेस बोली- 'पहले PM को ढूंढो, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा पर जवाब दो'

राहुल गांधी के गुमशुदगी वाले पोस्टर को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब और तेज हो गया है. BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के कथित विदेश वेकेशन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी कहां हैं और उनका कार्यक्रम क्या है. इस पर कांग्रेस की तरफ से नया जवाब सामने आया है. उत्तर प्रदेश के लिए नई जिम्मेदारी संभाल रहे राजेंद्र पाल गौतम ने BJP के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सवाल राहुल गांधी पर नहीं बल्कि सरकार के कामकाज पर होने चाहिए.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जो लोग राहुल गांधी को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं, उन्हें पहले प्रधानमंत्री को ढूंढना चाहिए और देश के बड़े मुद्दों पर जवाब मांगना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान पर दबाव का माहौल बनाया गया है और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी. राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी अगले एक से डेढ़ महीने के भीतर प्रदेश में ऊपर से लेकर गांव स्तर तक पूरा संगठन तैयार कर देगी. उन्होंने कहा कि इसी दौरान जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं और मुद्दे जुटाए जाएंगे और उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी. साथ ही चुनाव लड़ने वाले नेताओं की पहचान अभी से शुरू कर उन्हें तैयार किया जाएगा. राम मंदिर चंदा और कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रमुखता से उठाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास के साथ मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसी आस्था को चोट पहुंचाने का काम हुआ. उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और जनता के सामने पूरी सच्चाई आनी चाहिए।

PM मोदी को सेशेल्स ने दिया 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' अवॉर्ड

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स सरकार ने 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' अवॉर्ड से सम्मानित किया है. यह सेशेल्स का एक बड़ा सम्मान है, जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु बदलाव से लड़ाई और टिकाऊ विकास में बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया जाता है. यह सम्मान पीएम मोदी के उन प्रयासों को मान्यता देता है, जिनके जरिए उन्होंने क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन ग्रोथ और पर्यावरण सुरक्षा को लगातार बढ़ावा दिया है.यह अवॉर्ड पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही उस सोच को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी बराबर महत्व दिया गया है.

'दूसरों पर उंगली न उठाए पाक गिरेबान में झांके' : विदेश मंत्रालय

करारा जवाब

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने कराची में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत पर कई आरोप लगाए थे, जिसे भारत से रविवार (28 जून, 2026) को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने आरोपों को निराधार करार देते हुए इस्लामाबाद से कहा कि वह दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने देश में पनप रहे आतंकवादी ढांचे को खत्म करने पर ध्यान दे.भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार (28 जून, 2026) को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'हमने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर भारत पर लगाए गए पाकिस्तान के निराधार आरोपों से जुड़े रिपोर्ट्स देखे हैं. हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं.'

उन्होंने कहा, 'दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांककर देखे, तो ज्यादा अच्छा होगा. अपने देश की जमीन पर पनप रहे आतंकवादियों और मौजूद आतंकवादी ढांचों के खिलाफ उसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आंतकवाद को अपनी देश की नीति के एक साधन के रूप से इस्तेमाल करने की अपनी प्रवृति को भी खत्म करना चाहिए.'

भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान पाकिस्तान के उस दावे के एक दिन बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कराची में सिंध रेंजर्स के कपाउंड में हुए आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया. पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, यह आतंकवादी हमला शनिवार (27 जून, 2026) की रात कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स के भिट्टाई विंग हेडक्वार्टर पर हुआ. इस हमले में रेंजर्स के चार जवान मारे गए. वहीं, अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमले के खिलाफ ऑपरेशन करीब 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक चला, जिसमें छह आतंकवादी मारे गए और एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया. पाकिस्तान के अधिकारियों ने रेंजर हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली है।

मिड-डे मील से हटाया अंडा तो भाजपा पर भड़कीं महुआ मोइत्रा

कोलकाता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी केएमसी इलाके के स्कूलों में मिड डे मील से अंडे हटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि ज्यादातर बंगाली मांसाहारी हैं. साथ ही उन्हें सोया पसंद नहीं है. अब इस पर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है. नई-नई बनी बीजेपी की सरकार ने कोलकाता में स्कूलों के मिड डे मील को तैयार करने का काम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) को सौपा है. अब मील में अंडे की जगह राजमा दिया जाएगा. यह एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. टीएमसी ने सरकार पर बंगाल में शाकाहारी कल्चर थोपने का आरोप लगाया है. बंगाल के वित्तमंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने घोषणा की है कि प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील की लागत 6.78 प्रति रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कर दी जाएगी. इसकी सप्लाई की जिम्मेदारी इस्कॉन की रहेगी।

हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें स्थान पर भारत

दुनिया का सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान

दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची जारी हो चुकी है. हालांकि, इसमें कुछ ऐसे देश शामिल है, जो सबसे ज्यादा नीचे हैं. अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और लेबनान जैसे देशों में हालात काफी खराब बताए गए हैं. यह रिपोर्ट सिर्फ पैसे या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई बातों को देखकर तैयार की गई है. इसमें जीवन से संतुष्टि और सामाजिक हालात जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार कई देशों का स्कोर 4 से भी नीचे चला गया है, जो बताता है कि वहां के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं. खास तौर पर अफगानिस्तान का स्कोर सबसे कम है, जो इस सूची में सबसे नीचे है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, अफगानिस्तान 147वें स्थान पर है और उसका स्कोर सिर्फ 1.446 है. इसमें -2.594 की गिरावट दर्ज की गई है, जो सबसे ज्यादा है. इसका मतलब है कि वहां हालात तेजी से खराब हुए हैं. वहां की जिंदगी आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से प्रभावित है. इस सूची में भारत 116वें स्थान पर काबिज है.

अफ्रीका के देशों की स्थिति

सिएरा लियोन 146वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.251 है और इसमें -1.067 की गिरावट आई है. यह देश कई सालों से संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और ढांचे जैसी सुविधाओं पर दबाव बना हुआ है. मलावी 145वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.284 है और -0.829 की गिरावट दर्ज की गई है. यहां आर्थिक सीमाएं, मौसम से जुड़ी समस्याएं और संसाधनों की कमी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं. खासकर गांवों में हालात ज्यादा कठिन बताए जाते हैं. जिम्बाब्वे 144वें स्थान पर है और इसमें -1.481 की बड़ी गिरावट आई है. यहां लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता और मुद्रा की समस्या बनी हुई है. रोजमर्रा की जिंदगी अनिश्चित रहती है और रोजगार की भी कमी है. बोत्सवाना 143वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.464 है और -0.506 की गिरावट आई है. इसे आम तौर पर स्थिर देश माना जाता है, लेकिन अब यहां भी असमानता और आर्थिक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं.

मिडिल ईस्ट देशों की रैंकिंग

यमन 142वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.532 है, जिसमें -0.522 की गिरावट आई है. यहां लंबे समय से संघर्ष और मानवीय संकट चल रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है. लेबनान 141वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.723 है, जिसमें -1.208 की गिरावट आई है. यहां आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों में असंतोष बढ़ा है. रोजमर्रा की सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं.

इसी साल बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निर्वासन में रहते हुए बड़ा दावा किया है कि वह इसी साल अपने देश लौटेंगी. उन्होंने कहा कि उनकी वापसी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बहाली से जुड़ी है. एक विशेष ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध, अपने खिलाफ मौत की सजा, अंतरिम सरकार, बांग्लादेश की राजनीति, अल्पसंख्यकों पर हमलों और भारत में अपने निर्वासन के जीवन पर विस्तार से बात की. शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका का इस्तेमाल अवामी लीग को नेतृत्वविहीन करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मुझे मौत का डर नहीं है. 1975 में मैंने अपने माता-पिता, भाइयों और लगभग पूरे परिवार को खो दिया था. मुझ पर ग्रेनेड हमला भी हुआ, लेकिन हर साजिश को पार कर मैं जनता के साथ खड़ी रही।

आयरलैंड से सीरीज हारा भारत

दूसरे टी20 में 1 रन से हारी टीम इंडिया; 155 नहीं हुए चेज

आयरलैंड ने दूसरे टी20 में भारत को एक रन से हरा दिया है. इसके साथ ही आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से जीत ली है. लगातार 16 टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया कोई सीरीज हारी है. आयरलैंड ने भारतीय टीम को क्लीन स्वीप देकर इतिहास रच दिया है. आयरलैंड पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत से सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है. आयरलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए थे. जवाब में भारत निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी. आयरलैंड ने एक रन से दूसरा टी20 जीता. आयरलैंड ने सिर्फ एक रन से दूसरा टी20 जीता. इस तरह श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर अपनी पहली ही टी20 सीरीज हार गए. आयरलैंड से मिले 155 रनों के मामूली से लक्ष्य को भारत ने अपनी खराब बल्लेबाजी से पहाड़ जैसा बना दिया. टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. दोनों ओपनर बिना खाते खोले पवेलियन लौटे. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, दोनों को जय मूंदरा ने जीरो पर आउट किया. ईशान किशन 11 गेंद में 12 रन बनाकर रन आउट हुए. कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर फ्लॉप रहे. वह सात गेंद में दो चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

पावरप्ले में ही 35 रनों पर चार विकेट गिरे तो अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया. अक्षर ने काफी स्लो बैटिंग की. वह 18 गेंद में बिना कोई बाउंड्री लगाए सिर्फ 14 रन ही बना सके. तिलक वर्मा एक छोर पर डटे रहे. अब उनसे और शिवम दुबे से उम्मीद थी. दुबे 16 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए, क्योंकि तिलक तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे, और जरूरी रन रेट बढ़ता जा रहा था।

सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू कराने वाला दूसरा देश बना भारत

नई दिल्ली। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत ने इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले में सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है. शेडगे और यादव भारत के लिए टी20 डेब्यू करने वाले क्रमशः 120वें और 121वें खिलाड़ी हैं. टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू करवाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है.सूर्यांश शेडगे को नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेमेंट के तौर पर आयरलैंड सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में मौका मिला था. वहीं प्रिंस यादव ने कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. बताते चलें कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है. सूर्यांश शेडगे IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और भारतीय घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं. वहीं प्रिंस यादव इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 वनडे मैचों में 3 विकेट लिए थे.

पाकिस्तान है नंबर-1

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान ने अब तक सबसे ज्यादा 125 खिलाड़ियों का डेब्यू करवाया है. इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, क्योंकि सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव को टी20 डेब्यू कैप मिलने के बाद भारत के लिए 121 खिलाड़ियों ने टी20 डेब्यू कर लिया है.सूर्यांश और प्रिंस से पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले आखिरी खिलाड़ी हर्षित राणा था. उन्होंने जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. हर्षित उसके बाद 10 टी20 मैचों का अनुभव प्राप्त कर पाए हैं. हर्षित के डेब्यू के 513 दिनों के बाद भारत ने किसी खिलाड़ी को टी20 डेब्यू कैप थमाई है.

गौतम गंभीर की जगह रिकी पोंटिंग बनेंगे टीम इंडिया के कोच

नई दिल्ली। क्रिकेट में ऐसा रोज-रोज नहीं होता है, जब उस कप्तान को चंद महीनों बाद टीम से निकाल दिया जाए, जिसके अंडर टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता हो. यह हाल ही में भारत में हुआ है, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर नए टी20 कप्तान बन गए हैं. इस पर इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने प्रतिक्रिया देकर कहा है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उन्हें श्रेयस के नए टी20 कप्तान बनने की जानकारी मिली तो उन्हें लगा कि रिकी पोंटिंग भारतीय टीम के कोच बनने वाले हैं.अजिंक्य रहाणे के यूट्यूब चैनल पर माइकल वॉन ने कहा, "जब मैंने यह सुना तो मुझे लगा कि रिकी पोंटिंग टीम इंडिया के कोच होंगे, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी गजब है. वो बहुत अच्छे कप्तान हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं।

दोस्त ने नहीं चुकाया लोन तो बैंक खाली करेगा आपका खाता, गारंटर बनने का नुकसान

नई दिल्ली। कोई रिश्तेदार आपसे किसी लोन के लिए गारंटर बनने को कहे, क्योंकि 'यह तो बस एक औपचारिकता है' और भावनात्मक रूप से मदद करना अक्सर सही काम लगता है. लेकिन निजी रिश्तों में पैसे का मामला बहुत तेज़ी से उलझ सकता है, क्योंकि कभी-कभार किसी की मदद करना भले ही कोई समस्या न हो, लेकिन जोखिमों को पूरी तरह समझे बिना बार-बार पैसे उधार देना या लोन की गारंटी लेना चुपचाप आपकी अपनी आर्थिक स्थिरता को भी नुकसान पहुंचा सकता है. जाने या अनजाने में लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक लोन गारंटर बनने के बारे में है. बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ़ दिखावे की होती है. जबकि ऐसा नहीं है. जब आप किसी के लोन के लिए गारंटी देते हैं तो आप कानूनी तौर पर लोन चुकाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, अगर असल उधार लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है. अगर उधार लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुकाता, पेमेंट में देरी करता है या लोन का निपटारा ठीक से नहीं करता है तो लेंडर (लोन देने वाले) पैसे वसूलने के लिए गारंटर से संपर्क कर सकते हैं.इतना ही नहीं गारंटीशुदा लोन गारंटर की क्रेडिट प्रोफाइल और भविष्य में लोन लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि वित्तीय योजनाकार बार-बार लोगों को भावनात्मक बाध्यता के कारण गारंटी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचने की सलाह देते हैं।

अब एक साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रैच्युटी

नई दिल्ली। नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत, फिक्स्ड-टर्म

कर्मचारियों (FTE) को ग्रैच्युटी पाने के लिए अब पांच साल तक का इंतजार नहीं करना होगा. नियमों में बदलाव के चलते केवल एक साल की निरंतर सर्विस के बाद ही ये ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे. पहले कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कर्मचारी को काम पर रखती थी, तो उसे स्थायी या परमानेंट कर्मचारियों जैसे लाभ नहीं मिलते थे. अब 'फिक्स्ड-टर्म' के तहत एक तय समय (1 साल या 2 साल) के लिए लिखित कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारी सीधे कंपनी के पेरोल पर रखे जाएंगे. यानी उनकी सैलरी, छुट्टियां और अलाउंस स्थायी कर्मचारियों के जैसे ही मिलेंगे. मौजूदा कानून (Payment of Gratuity Act, 1972) के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी को ग्रैच्युटी तभी मिलती है, जब वह 5 साल तक की सर्विस पूरी कर लेता है. FTE के तहत, अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 1 साल 3 महीने का है, तो आपको पूरे 15 महीनों की ग्रैच्युटी मिलेगी. यह उन लोगों के लिए खुशी की बात है, जो खासतौर पर प्रोजेक्ट-बेस्ड काम करते हैं.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा अमीरों का पलायन

तिजोरियों में बंद होने लगे 100-200 के नोट

हाल के दिनों में 100 और 200 रुपये के नोटों को लेकर एक नया ट्रेंड देखने को मिला है. लोग पहले के मुकाबले अपने घरों में ज्यादा नकद पैसे रखने लगे हैं. यहां हम 500-2000 की बात नहीं कर रहे हैं. देखा जा रहा है कि 100- 200 जैसे छोटे नोटों की मांग बढ़ गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में नोटों की कोई कमी है, बल्कि कई लोग एहतियात के तौर पर अपने पास ज्यादा कैश रखना पसंद कर रहे हैं.

कैश क्यों रख रहे हैं लोग?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लोगों ने सावधानी के तौर पर नकदी अपने पास रखना शुरू किया है. ऐसे समय में कई लोग डिजिटल पेमेंट के साथ-साथ कुछ नकद राशि भी घर में रखना सुरक्षित मानते हैं. एक्सपर्ट्स की माने तो जब दुनिया में आर्थिक या भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो लोग अपनी जरूरतों के लिए पहले से कैश रखने लगते हैं.

कोविड के बाद लोग हुए अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में लोगों के पास मौजूद नकदी में बढ़ोतरी की रफ्तार कोविड-19 महामारी के बाद सबसे तेज रही है. इससे पता चलता है कि एहतियात के तौर पर कैश रखने की प्रवृत्ति फिर से बढ़ रही है. हालांकि, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम या डिजिटल भुगतान पर लोगों का भरोसा कम हुआ है. U P I और डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ लोग थोड़ी नकदी भी अपने पास रखना पसंद कर रहे हैं.

क्या 100- 200 की कमी है?

इस सवाल का सीधा जवाब है, नहीं. फिलहाल 100 और 200 रुपये के नोटों की कोई ऑफिशियल कमी नहीं बताई गई है. भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग सिस्टम में भरपूर करेंसी है. बढ़ती मांग का कारण सिर्फ लोगों की एहतियात के तौर पर नकदी रखने की आदत माना जा रहा है.

क्या घर में कैश रखना चाहिए?

रोज के काम और जरूरतों के लिए तो कैश रखना ही चाहिए. इसके अलावा इमरजेंसी जैसी स्थिति के लिए भी सीमित मात्रा में नकदी रखना सही रहता है. लेकिन बहुत ज्यादा कैश घर में रखना सुरक्षित नहीं माना जाता है. आप अपने पैसे बैंक अकाउंट या ऑनलाइन बैंकिंग में ही रखें.

वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों ने लिखा नया इतिहास

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है. आमिर जांगू और कप्तान रॉस्टन चेज ने 401 रनों की पार्टनरशिप कर इतिहास रच दिया. जांगू और चेज दुनिया की ऐसी पहली जोड़ी बन गई हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में छठे विकेट के लिए 400 से ज्यादा रनों की साझेदारी की है. आमिर जांगू ने 233 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जबकि रॉस्टन चेज डबल सेंचुरी लगाने से चूक गए. श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के 5 विकेट 168 रन पर गिर गए थे. इसके बाद आमिर जांगू और रॉस्टन चेज ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब पसीना बहाने पर मजबूर किया. दोनों ने 100 ओवर से भी ज्यादा एकसाथ बैटिंग की और 401 रन जोड़ डाले. उनकी इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप के दम पर वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 626 रन बनाकर पारी घोषित की.

साप्ताहिक शहर सत्ता

भूपेश ने जिलाध्यक्षों से कहा- जनता की लड़ाई आक्रामक तरीके से लड़ें

प्रशिक्षण शिविर के समापन में शामिल होंगे पवन खेड़ा

रायपुर। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के 8वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन के गुर सिखाए। प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए जिला अध्यक्षों से कहा, वे आक्रामक तरीके से जनता की लड़ाई लड़ें।

खड़गे और राहुल गांधी ने आपको संगठन की शक्ति दी है, उसका उपयोग कर आप मोदी सरकार और राज्य सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ मुखरता से आवाज उठायें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की पांच साल की योजनाओं, कांग्रेस की रीति-नीति, इतिहास, देश के विकास में कांग्रेस का योगदान पर व्याख्यान दिया। उन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाकर जनता का दिल जीतने का प्रयास करें। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने तथा अल्पसंख्यक विभाग के अमीन मेमन, आदिवासी अधिकार, अल्पसंख्यक कल्याण तथा जल, जंगल, जमीन पर व्याख्यान दिया।

नेताम के बयान पर पलटवार

कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर को लेकर मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की ट्रेनिंग देती है, गोडसे की विचारधारा की नहीं। यदि रामविचार नेताम कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में एक घंटे भी बैठ जाएं तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और भाजपा छोड़ देंगे।

चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, शिविर में जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रशिक्षण के जरिए संगठन को मजबूत करने के साथ राज्य सरकार के खिलाफ जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे जनता की समस्याओं और मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने रख सकें। यह शिविर केवल संगठन मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी हिस्सा है। दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण के बाद सभी जिला अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष अर्जुन की तरह लक्ष्य साधकर कौरव सेना का मुकाबला करेंगे। हमारा लक्ष्य मछली की आंख है और भाजपा के छल-प्रपंच से प्रदेशवासियों को दूर करना है।

ढाई साल में एक भी मौलिक योजना नहीं ला पाई सरकार : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, साय सरकार ने ढाई सालों में या तो कांग्रेस सरकार के समय चलाई जा रही

योजनाओं का नाम बदला है या फिर उन योजनाओं को दुर्भावनापूर्वक बंद किया है। सरकार ढाई साल में प्रदेश के हित में एक भी मौलिक योजना चला पाने में फेल साबित हुई है। सरकार के पास जनकल्याण विजन का अभाव साफ दिखता है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने ढाई साल में छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। साय सरकार पिछली सरकार की इन 20 महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद किया। बंद योजनाओं में 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ योजना बंद कर दिया। राजीव मितान योजना, गोधन न्याय योजना, रीपा, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना, बेरोजगारी भत्ता, मुख्यमंत्री कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी, महिला समूहों की ऋण माफी, सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि, सीएम छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि, कोदो-कुटकी-रागी खरीदी, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मुख्यमंत्री महतारी दुलार, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, धरसा विकास, शहरी गरीबों को पट्टा एवं आवास, छत्तीसगढ़िया ओलिंपिक, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को बंद किया। यह सरकार दुर्भावना वाली सरकार है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में क्षमता नहीं है कि वह कोई नई योजना कर सके। वह कांग्रेस सरकार के समय चलाई जा रही 10 योजनाओं के नाम बदल कर झूठी वाहवाही लेने पर लगी है।

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने 45 दावेदार

रायपुर। प्रदेश युवक कांग्रेस चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में 45 युवा नेताओं की सूची जारी की गई है, जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं। इनमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र आदित्य, निकाय अध्यक्ष निखिलकांत साहू, विनयशील गुप्ता और अन्य हैं। युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई ने प्रदेश के चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं का इंटरव्यू लिया। इसमें 45 युवा नेताओं के कामकाज को उत्कृष्ट माना गया है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पात्र नेताओं में जीशान कुरैशी, तुकाराम चंद्रवंशी, भावेंद्र गंगोत्री, भावेश शुक्ला, अनिमेष सिंह, आदिल आलम खेरानी, मानव देशमुख, सोनिका पोर्ते, जसमीत शर्मा, नीरज घोरे, खुशबू आदित्य वैष्णव, रूबी तिवारी, शैलेंद्र बंजारे, गौरव मिश्रा, प्रशांत बोकाडे, हनी परमीत बग्गा, अमित शर्मा, लोकेश वशिष्ठ, विनयशील गुप्ता, कपिलकांत, सतेंद्र चेलक, नजरुल इस्लाम, मृदुला बास्कर, गुलजेब अहमद, आशिका कुजूर, प्रीति वैष्णव, प्रीतिका विश्वकर्मा, गणेश दुग्गा, मनहरण वर्मा सहित अन्य नाम शामिल हैं।

आज होगी स्क्रूटनी

अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 जून को स्क्रूटनी होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत, कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष विनयशील गुप्ता, महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष निखिलकांत साहू और बलौदाबाजार-भाटापारा के जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र बंजारे प्रमुख दावेदार हैं।

जुलाई के अंतिम सप्ताह में होंगे चुनाव

युवा कांग्रेस चुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद अब चुनाव जुलाई के आखिरी सप्ताह में होंगे। हालांकि अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं के नाम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जुड़े गए हैं। ऐसे में ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव के लिए उन्हें दावेदारी करने में हो रही दिक्कतों को दूर करने हल निकाला जा रहा है।

मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटा रही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हो गये, लेकिन मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम नहीं घटा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में 31 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जो क्रूड ऑयल के दाम 116 डॉलर प्रति बैरल था आज 70 डॉलर है। इसमें प्रति बैरल लगभग 46 डॉलर की कमी हुई, लेकिन देश के भीतर किसान मजदूर युवा व्यापारी उद्योगपतियों को आज भी महंगी दरों पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां मिलकर आम जनता की जेब से पेट्रोल डीजल के माध्यम से प्रति लीटर 35 रुपए से अधिक की कमाई कर रही है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से लगभग 32 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और पेट्रोलियम कंपनियों को मुनाफाखोरी में छूट देने से बीते 6 महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने लगभग 47000 करोड़ रुपए की कमाई की है और गरीब जनता महंगाई की मार के बोझ तले दबते जा रही है। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफाखोरी गठबंधन को जिम्मेदार है। पश्चिम एशिया तनाव शुरू होने से पहले क्रूड आयल के जो दाम थे, आज उससे भी कम हो गये है। जब क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा हुआ तो मोदी सरकार ने 10 दिनों के भीतर डीजल-पेट्रोल के दाम 6-6 बार दाम बढ़ाये, अब क्रूड आयल के दाम गिरने पर भी लूट जारी है।

सभी विधानसभा क्षेत्रों से तीन-तीन प्रमुख कार्यकर्ताओं को किया गया प्रशिक्षित

कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में निपुण बनाने के लिए देशव्यापी अभियान चला रही है। बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बैठक हुई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि भाजपा एक कार्यकर्ता-आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं की योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही लगातार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से चिन्हित किए गए तीन-तीन प्रमुख कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक जाकर अन्य साथियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही और प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हमारे कार्यकर्ता हर क्षेत्र में सक्षम और योग्य बनें। उनका संगठनात्मक और वैचारिक विकास हो, ताकि एक योग्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हो सके। कार्यकर्ताओं के प्रबोधन और प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया भाजपा की एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कौशल सिखाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यशाला में कहा, भाजपा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि इसके रचनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रम पूरे वर्षभर चलते रहते हैं।

आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था : सच्चिदानंद उपासने

रायपुर। देश में लगाए गए आपातकाल की 51 साल पूरे होने पर बुधवार को आरंग के स्थानीय नवीन विश्राम गृह में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि उस दौर में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का खुलकर दमन किया गया था। उपासने ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल घोषित किया था। इसके बाद करीब 21 महीनों तक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रभावित रहीं। चुनाव स्थगित कर दिए गए, नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए और सरकार की आलोचना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी।

लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री साय

आपातकाल हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सदैव सजग रहने की प्रेरणा देता है : डॉ. रमन सिंह

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित डीडीयू ऑडिटोरियम में आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। गरिमामयी समारोह में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष पर आधारित स्मारिका "आपातकाल के योद्धा" का विमोचन किया तथा आपातकाल पर आधारित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन मूल्य है, जिसे समझने और निभाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा का काल था, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को स्मरण करते हुए कहा कि उन लोगों ने जेल, यातनाओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोकतांत्रिक आदर्शों को जीवित रखा। मुख्य वक्ता श्री कुमार ने कहा कि इतिहास को याद रखना केवल अतीत को जानना नहीं है, बल्कि उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश की एकता, अनुशासन और सामाजिक समरसता को मजबूत करें तथा नशामुक्त और स्वच्छ समाज के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों ने हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है और इन्हीं मूल्यों के आधार पर देश - दुनिया में अपनी पहचान को और मजबूत कर सकता है। उन्होंने युवाओं से "राष्ट्र प्रथम" की भावना को जीवन में अपनाने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र, ज्ञान और धर्म प्रथम की भावना ही भारत की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या सृष्टि का वह स्थान है जो सदैव पूजनीय रहेगा और सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह कालखंड है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष, त्याग और जेल जीवन की कठिनाइयों को याद करते हुए कहा कि इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। श्री साय ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल स्मरण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सचेत करना है ताकि वे समझ सकें कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती हमेशा से संघर्ष, संस्कृति और परंपरा की भूमि रही है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराने के लिए इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना प्रशंसनीय पहल है।

ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सोलर बिजली निर्धारित दर पर खरीदी जाएगी

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त (सरप्लस) सोलर बिजली की खरीदी दर (बायबैक रेट) तय की है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस दर को अपनाने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ से मिली जानकारी के अनुसार, निर्धारित दर को अंतिम अनुमोदन और मंजूरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के पास भेज दिया गया है। आयोग से हरी झंडी मिलते ही उपभोक्ताओं को उनकी अतिरिक्त बिजली की राशि अगले बिजली बिलों में क्रेडिट (छूट) के रूप में दिखाई देने लगेगी। पावर कंपनी ने इसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत, सोलर संयंत्र से जितनी बिजली बनती है, उसका सबसे पहले उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत में समायोजन (अडजस्टमेंट) किया जाता है। यदि उपभोक्ता की जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है और वह ग्रिड में वापस जाती है, तो उसकी बची हुई यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती चली जाती है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 बनी दूरस्थ अंचलों के लोगों की बड़ी उम्मीद

एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त मिली, हितग्राही की समस्या का हुआ त्वरित समाधान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन गई है। विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एक फोन कॉल के माध्यम से उनकी शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। सुकमा जिले के जनपद पंचायत छिंदगढ़ अंतर्गत ग्राम भोपावाड़ा निवासी श्री जोगा हिरमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की दूसरी किस्त का भुगतान लंबित होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि हितग्राही का आवास निर्धारित स्तर तक पूरा हो चुका है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए दूसरी किस्त के भुगतान के लिए एफटीओ जारी किया गया और राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा कर दी गई।

दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा सुशासन

यह उदाहरण बताता है कि सीएम हेल्पलाइन 1076 अब केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान का मजबूत तंत्र बन चुकी है। दूर-दराज़ के गांवों में रहने वाले नागरिक भी अब अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचा रहे हैं और उनकी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार की इस पहल से आम लोगों का शासन-प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ बना देश का अग्रणी राज्य

रायपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने अभियान के शुरुआती मात्र 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72 प्रतिशत पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश ने न केवल हितग्राहियों के पंजीयन में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, बल्कि प्री-रजिस्टर्ड हितग्राहियों के निराकरण में भी सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक उपलब्धि अर्जित की है। यह उपलब्धि महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, मैदानी अमले तथा सभी संबंधित हितधारकों के समन्वित और समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

विशेष अभियान के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा ने 96 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि मातृ एवं शिशु कल्याण के प्रति जिले की संवेदनशीलता, सक्रियता और प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रतिबिंबित करती है। मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मातृ कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृत्व के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत प्रथम जीवित संतान के जन्म पर पात्र महिलाओं को 5,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

कल-कल बहता झरना और लोककथाओं का अद्भुत संगम पर्यटकों को करता है मंत्रमुग्ध

प्रकृति की गोद में बसा जशपुर का अनुपम पर्यटन स्थल 'रानीदाह'

रायपुर। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक संपदा, घने वनों, पहाड़ियों और मनमोहक जलप्रपातों के लिए पूरे प्रदेश में विशेष पहचान रखता है। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों में शामिल है रानीदाह जलप्रपात, जो अपनी अलौकिक सुंदरता, शांत वातावरण और ऐतिहासिक लोककथाओं के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। जशपुर नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्यटन स्थल प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफी के शौकीनों और रोमांच पसंद पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

रानीदाह तक पहुँचने का सफर भी अपने आप में यादगार अनुभव है। हरियाली से आच्छादित पहाड़ियों, घने साल के जंगलों और घुमावदार खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए जैसे ही पर्यटक इस स्थल पर पहुँचते हैं, सामने ऊँची चट्टानों से गिरती दूधिया जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों का मधुर कलरव मन को सुकून से भर देता है। विशेषकर वर्षा ऋतु में यह जलप्रपात अपने पूरे वैभव में दिखाई देता है, जब पानी अनेक धाराओं में विभाजित होकर ऊँचाई से नीचे गिरता है और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है।

लोककथा से जुड़ी है रानीदाह की पहचान

रानीदाह केवल प्राकृतिक सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोककथाओं और जनश्रुतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रचलित मान्यता के अनुसार, बहुत समय पहले ओडिशा की राजकुमारी रानी शिरोमणि इन पहाड़ियों तक पहुँची थीं। जब उनके पिता और पाँच भाई उनका पीछा करते हुए यहाँ आए, तब रानी ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इसी गहरी खाई में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी से इस स्थान का नाम रानीदाह पड़ा, जिसका अर्थ है 'रानी का जलप्रपात'। झरने के समीप स्थित कुछ चट्टानों को आज भी स्थानीय लोग 'पाँच भैया' के नाम से जानते हैं, जिन्हें रानी के पाँच भाइयों का प्रतीक माना जाता है। यह लोककथा आज भी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रानीदाह जलप्रपात अपने शांत वातावरण, स्वच्छ प्राकृतिक परिवेश और मनोहारी दृश्यों के कारण परिवारों, युवाओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के साथ-साथ यादगार फोटोग्राफी और ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं।

कृति सैनन को हुआ ब्रेकअप?

मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर कृति के बायफ्रेंड कबीर बहिया

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कृति सैनन इन दिनों फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. 19 जून को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. फिल्म में रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं. 'कॉकेटल 2' के बीच अब कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

दरअसल, कृति सेनन का नाम पिछले काफी समय से बिजनेसमैन कबीर बहिया के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है और उनकी वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं. इतना ही नहीं, कबीर बहिया हाल ही में कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे, लेकिन अब कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के ब्रेकअप की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है.

लड़की के बेहद करीब दिखे कबीर बहिया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कबीर बहिया की एक तस्वीर सामने आई है, जिसने कबीर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में वो उस लड़की के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं. ये किसी पार्टी की फोटो लग रही है. कबीर के साथ नजर आ रही ये लड़की कौन है, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इस फोटो के वायरल होते ही कयास लगाए जाने लगे कि कृति और कबीर का ब्रेकअप हो चुका है. हालांकि, कृति और कबीर की ओर से कभी भी ना तो रिश्ते को और ना ही अब ब्रेकअप को ऑफिशियली कंफर्म किया है.

कौन हैं कबीर बहिया?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कबीर बाहिया, वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसे उन्होंने 2020 में बनाया था. उनकी फर्म एयरलाइन रिप्रिजेंटेशन सर्विस में स्पेशलाइज रखती है. वो एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता कुलजिंदर बहिया एक प्रमुख ब्रिटिश ट्रैवल एजेंसी साउथॉल ट्रैवल के मालिक हैं. कबीर अपने पूरे परिवार के साथ ब्रिटेन में रहते हैं. कबीर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के रिश्तेदार हैं. साक्षी के साथ कबीर ने कई तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई हैं.

'लॉक अप 2' में सुनीता की एंट्री से टेंशन में थे गोविंदा

रियलिटी शो लॉकअप 2 का अगाज हो गया है. शो में सुनीता आहूजा कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं. हाल ही में सुनीता आहूजा ने खुलासा किया कि कई रियलिटी शोज के ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने 'लॉक अप सीजन 2' को ही क्यों चुना. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि शो में हिस्सा लेने के उनके फैसले पर पति गोविंदा का क्या रिएक्शन था. सुनीता आहूजा ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 'राइज एंड फॉल', 'द 50', 'ट्रेटर्स' और 'अलायंस' जैसे कई रियलिटी शोज के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने 'लॉक अप सीजन 2' को चुना. उन्होंने कहा कि एकता कपूर के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि इस शो में उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा. सुनीता ने आगे कहा कि उन्हें 24 घंटे कैमरों के बीच रहने से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जैसी हैं, वैसी ही दुनिया के सामने रहना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा कि वो किसी के लिए खुद को बदलने वाली नहीं हैं और इस शो के जरिए लोग असली सुनीता आहूजा को जान पाएंगे.

कोविड के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस हैं रश्मिका

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपकमिंग फिल्म 'मायसा' से नया लुक जारी किया गया है, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है. कोविड-19 के बाद से वो इकलौती अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी और 3 फिल्मों से तो उन्होंने हैट्रिक ही मार दी और वह 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती अभिनेत्री बन चुकी हैं।

कोविड-19 के दौर में जहां बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज हो रही थी तो उसे फ्लॉप का सामना करना पड़ रहा था लेकिन उसी बीच दो फिल्में रिलीज की गईं पहली 'पुष्पा द राइज' और दूसरी 'केजीएफ 2' तो दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था. 'पुष्पा' ने 2021 में अकेले घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. इस फिल्म के बाद रश्मिका नेशनल क्रश बन गईं. अल्लू अर्जुन और रश्मिका की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था.

3 ब्लॉकबस्टर से लगाई हैट्रिक

'पुष्पा द राइज' के बाद रश्मिका मंदाना लाइमलाइट में आ गईं और फिर इसके सीक्वल का लोगों के इंतजार होने लगा. 2022 में 'सीता रामम' से भी सभी का ध्यान खींच लिया. इसके बाद एक्ट्रेस की झोली में कई फिल्में आईं और उन्होंने महज 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ही हैट्रिक मार दी. वह कोविड 19 के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गईं. रश्मिका मंदाना ने 'सीता रामम' के बाद फिल्म 'एनिमल' (2023) में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 915 करोड़ का कलेक्शन दुनियाभर में किया. इसके बाद वह 'पुष्पा द रूल' (2024-25) में नजर आईं. इसने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 1742 करोड़ का बिजनेस किया. अभी इसका क्रेज कम हो पाता कि इसके बाद सिनेमाघरों में आई 'छावा' (2025). इसने दुनियाभर में 807 करोड़ कमाए.

'मिर्जापुर' द मूवी से बाहर हुए विक्रांत मैसी, कर रहे अफसोस

'मिर्जापुर: द मूवी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सीरीज 'मिर्जापुर' को लोंगो ने खूब पसंद किया था. इसी बीच हाल ही में विक्रांत मैसी ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को लेकर दिल की बात कही. उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि शो में उनके किरदार 'बबलू पंडित' को पहले ही सीजन में मार दिया गया. वहीं, हाल ही में रिलीज हुए 'मिर्जापुर: द मूवी' के टीजर से भी साफ हो गया कि फिल्म में उनकी जगह अब जितेंद्र कुमार नजर आएंगे.हाल ही में एफएलओ बैंगलोर ऑफिशियल को दिए इंटरव्यू में विक्रांत मैसी ने 'मिर्जापुर' के दिनों को याद किया. विक्रांत कहा, 'काश उन्होंने मुझे मारा न होता. बबलू पंडित की कहानी थोड़ी और आगे बढ़नी चाहिए थी.' विक्रांत ने बताया कि जब उन्होंने इस शो की शुरुआत की थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका किरदार इतना बड़ा और गहरा असर छोड़ेगा. उन्होंने बताया कि शो में कुछ फीमेल मेंबर्स भी थीं, लेकिन कास्ट और क्रू का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा मेल का था.

विक्रांत ने बताया कि जिस दिन शो आया, वो लखनऊ में अपनी फिल्म 'रामप्रसाद की तेरहवीं' की शूटिंग कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं सुबह 6:30 बजे सेट पर पहुंच गया था. लेकिन शाम होते-होते लोकेशन के बाहर भारी शोर सुनाई देने लगा. डायरेक्टर और टीम को शूटिंग करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि बाहर 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी. हर तरफ खबर फैल गई थी कि बबलू भैया यहां आए हुए हैं.' 'मिर्जापुर' में विक्रांत मैसी ने अली फजल के ऑनस्क्रीन भाई 'बबलू पंडित' का किरदार निभाया था. साल 2018 में रिलीज हुई 'मिर्जापुर' को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली और अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं.वहीं, 'मिर्जापुर' अब उन चुनिंदा भारतीय वेब सीरीज में शामिल हो गई है, जिसे बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में लाया जा रहा है. 'मिर्जापुर: द मूवी' की कहानी साल 2018 की टाइमलाइन पर बेस्ड है, इसलिए इसमें कई ऐसे पॉपुलर किरदारों की वापसी होगी, जिनकी वेब सीरीज में मौत हो चुकी थी. फिल्म में श्रिया पिलगांवकर एक बार फिर स्वीटी गुप्ता के किरदार में नजर आएंगी, जबकि दिव्येंदु भी मुन्ना भैया बनकर वापसी कर रहे हैं. हालांकि, 'मिर्जापुर: द मूवी' में बबलू पंडित के किरदार में विक्रांत मैसी नहीं, बल्कि 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार नजर आएंगे. फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर में उनकी पहली झलक भी देखने को मिल चुकी है.

ओटीटी पर छाई 15 साल पुरानी वेब सीरीज

कुछ फिल्में और सीरीज़ ऐसी होती हैं, जो रिलीज़ हुए सालों बाद भी दर्शकों और फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं. उनकी कहानी, किरदार और खास पलों का जादू समय के साथ फीका नहीं पड़ता. आज हम आपको एक ऐसी ही सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 15 साल पुरानी होने के बावजूद अब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में है. आइए जानते हैं, यह सीरीज़ कहां स्ट्रीम हो रही है.दरअसल, इस सीरीज का नाम है 'गेम ऑफ थ्रोन्स'. इस सीरीज का पहली सीजन साल 2011 में रिलीज हुआ था. ये एक अमेरिकी टीवी सीरीज है, जो George R. R. Martin की किताब A Song of Ice and Fire पर बेस्ड है.बता दें, इस सीरीज के टोटल 8 सीजन रिलीज हो चुके हैं और इसमें टोटल 73 एपिसोड हैं. इस सीरीज में कई कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है।

वीरांगना दुर्गावती ने छत्तीसगढ़ में भी किया था अपने शौर्य का प्रदर्शन

डा. वेदवती मंडावी

वीरांगना महारानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को कालिंजर में हुआ था। आज से लगभग 480 साल पूर्व नर्मदा नदी के किनारे गढ़ मंडला नामक गोंडवाना राज्य विशाल भूभाग में फैला था, जिसमें कुल 52 गढ़ एवं 57 परगना थे। इस साम्राज्य में प्रतापी राजा संग्राम शाह थे। जिनके पुत्र दलपत शाह और कुल वधू दुर्गावती थीं। उन्होंने अपनी पुत्री को वीरों की तरह तलवार चलाना, तीर कमान चलाना और घुड़सवारी करना सिखाया था ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। कुंवर दलपत शाह भी अत्यंत सुंदर, गठीला तथा परमवीर था। उसका शौक शेरों का शिकार करना था। कीर्ति वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह कुंवर दलपत शाह के साथ कर दिया। 7 वर्षों के सुंदर वैवाहिक जीवन के उपरांत दलपत शाह की मृत्यु हो गई। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक गोंडवाना राज्य का संचालन किया। रानी दुर्गावती की राज्य सीमा के अनुसार सागर, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, राजनांदगांव जिले का संपूर्ण भाग, बिलासपुर, नागपुर जिला का उत्तरी भाग, भंडारा जिला, होशंगाबाद आदि उनके अधीन राज्य में था।

इनके 52 गढ़ में ग्रामों की संख्या अधिकतम 750 और कम से कम 350 गांव की संख्या थी। गोंडवाना राज्य धन-धान्य से परिपूर्ण था अतः अन्य पड़ोसी राज्यों के राजा दुर्गावती से बार-बार युद्ध करते थे मालवा के राजा बाज बहादुर ने तो तीन बार युद्ध किया और हार गया। दुर्गावती मुगल बादशाह अकबर की समकालीन शासिका थी और उनके प्रमुख सेनापति आधार सिंह था। अकबर बादशाह को दुर्गावती की बहादुरी एवं सुंदरता का पता चल चुका था तब उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत गोंडवाना साम्राज्य को आधिपत्य करने अपने सेनापति आसफ खान को भेजा। पहले तो आसफ खान ने दुर्गावती को मनाने का प्रयास किया, किंतु असफल होने पर उन्होंने 1564 में 6000 घुड़ सवार तथा 20 हजार पैदल सेना की फौज भेज कर गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया।

23 जून 1564 की सुबह दोनों सेनाओं का सामना हुआ इस युद्ध में महारानी स्वयं युद्ध का संचालन कर रही थी। इसी समय उनका पुत्र वीर नारायण शत्रु से लड़ते हुए घोड़े से गिर गए। रात्रि होने पर जब सभी तरफ की सेनाएं अपने-अपने खेमे में विश्राम कर रहे थे तब रानी सुरक्षित युद्ध की योजना बना ली थीं। किंतु किसी ने यह भेद शत्रु तक पहुंचा दिया। जिसके कारण युद्ध के मैदान में महारानी अपने शत्रुओं से घिर गईं। 24 जून की मैदानी लड़ाई में एक तीर अचानक उनकी आंख में लगी जिसे रानी तिनके की तरह निकाल फेंकी। किंतु दूसरा तीर लगने पर उन्हें लगा कि मुगल के हाथों मैं मृत्यु को वरण करने से अच्छा है कि वह अपने हाथों से स्वयं को कटार भोंककर इच्छा मृत्यु को वरण कर लिया। कहते हैं की उनका स्वामी भक्त हाथी सरमन नीचे गिरी हुई रानी को लेकर बैठ गया और किसी को छूने तक नहीं दिया। नरई नाले के पास उसी जगह पर रानी की समाधि आज भी गोंडवाना साम्राज्य की विशालता का प्रतीक है।

माता सीता ने स्नान किया था इस कारण नाम सीता नहानी

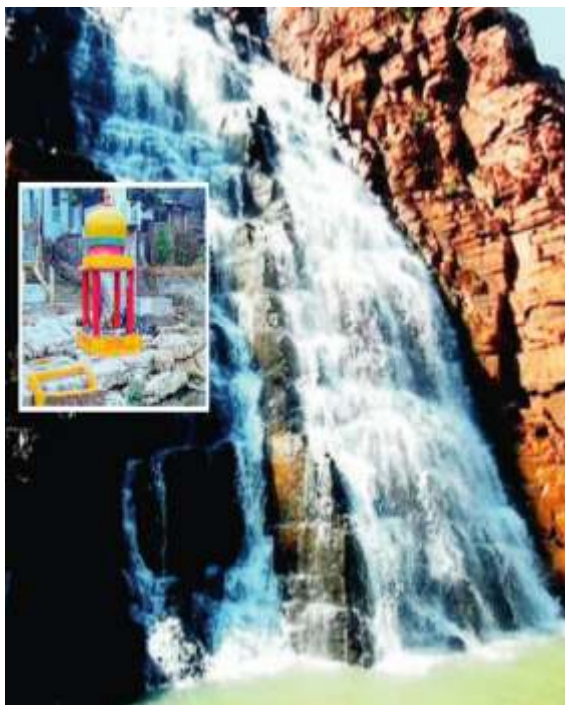

कमलेश यादव

छत्तीसगढ़ में राम वन गमन मार्ग चिन्हांकित किए गए हैं, लेकिन यहां का इतिहास वर्षों पुराना है। अनेक किंवदंतियों और नामकरण से प्रामाणिकता की पुष्टि भी होती है। राम वन गमन मार्ग का पड़ाव बस्तर के अनेक स्थानों पर देखी जाती है। कई स्थानों का नामकरण, शिलालेख और पुरातात्विक महत्व के स्थल आज भी पौराणिक काल के साक्षी के रूप में विद्यमान हैं 1 कहा जाता है कि दंतेवाड़ा से प्रभु श्रीराम तीरथगढ़ पहुंचे थे। जगदलपुर से 40 कि मी दूर स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रभु श्रीराम के प्रवास के संबंध में भी लोककथाएं प्रचलित हैं। तीरथगढ़ में कांगेर नदी सघन वनों और दुर्गम घाटियों के बीच एक मनोरम जलप्रपात बनाती है। यहां कांगेर नदी का पानी 300 फीट नीचे एक कुंड में गिरता है। मान्यता है कि इस कुंड में माता सीता ने स्नान किया था, इसलिए इसे सीता नहानी के नाम से भी जाना जाता है।

अब दिखाई नहीं देते गांवों में कुआं टेंड़ा रहट

डा. नीलकंठ देवगन

हले पीने का पानी का प्रमुख साधन होता था कुओं। जमीन में खोदा गया गहरा गड्ढा जिससे रस्सी बाल्टी के जरिये पानी निकाला जाता था। धंसकने से बचाने दीवाल में पत्थर या ईंट लगा दिया जाता था। हर गांव शहरों में कुएं होते थे। कुएं का पानी शुद्ध, ताजा होता था। अब हर गांव शहरों में चल बोरिंग की सुविधा हो गई है, विद्युत पंप लग गए है। कुओं का उपयोग कम होता गया और अब तो कुएं दिखते नहीं है। पट गये या उन्हें डंक दिया गया। कुजां से पानी निकालने में कसरत हो जाती थी। गगरी, घड़ा या होला सिर पर रखकर लाने से
महिलाओं के शरीर का संतुलन बना रहता था।
टेड़ा कुएं से पानी निकालने का पारंपरिक ग्रामीण पद्धति होती थी। इसमें लंबे बांस के सिरे पर बाल्टी बांधकर एक सहते के माध्यम से पानी ऊपर खींचा जाताथा। सब्जी बड़ी की सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता था।
साट कुएं से पानी निकालने और खेतों की सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका होता था। इसमें बेलों द्वारा घुमाया जाने वाला लोहे का गोलाकार पहिया होता था जिसमें बाल्टियों या मोटे टीन के डिब्बों की श्रृंखला होती जो कुएं से पानी भरकर खेतों में पहुंचाती। अब कुएं ही नहीं तो टेंड़ा और रहट कहां से होंगे ? यांद कहीं हैं भी तो उनमें मोटर पंप डाल दिये गये हैं।

बुड़े निही ते पाय के नाव होगे बुड़ेनी

लोमश कुमार ध्रुव

राजिम नगरी ले 48 कि मी दूरी म बुड़ेनी गांव हे। पहली ए जगा ह जंगल झाड़ी ले घिरे रीहिस। जंगली जानवर मन के बसेरा रीहिस। पैरी नदिया के तीर में बसे हे गांव ह। जादा घर के छानी नी रोहिस। पुरा पानी में नदिया ह बढ़त गिस, अऊ वोकर खड़ ह घूरत धूरत गांव तीर में आगे। धीरे धीरे अइसे होगे कि चौमास म गांव के चारों मुड़ा पानी में घिर जाए त संसों हो जाय कभु गांव ह बुड़ जाहि का तब जुन्ना सियान मन कहय हमर सती माता के किरपा ले बाबू हो हमर ए गांव ह बुड़े निही कहय।

जुन्ना सियान मन ल पक्का भरोसा रीहिस कि माता सती के दया मया ले हमर गांव कभु नी बुड़े। फेर पुरा पानी आवय त लईका जवान मन ल डर हो जाय। तभो ले डर के मारे ऊहा ले उसल के थोरीक दूरीहा में बसे लगिन। पहली वो गांव के कोनो नाव नी रोहिस। फेर बस्ती ल बुड़े निही कहय। धीरे धीरे बोमे हो अक्षर ह लोप होगे अऊ गांव के नाव बुड़ेनी होगे। अब इही नाव ह सबर दिन बर घरागे अऊ चलन में आगे। अभी घलव ओ जुन्ना डीही के चिन्हारी हावय। सती माता के किरपा ले आज तक गांव ह कभु नी बुड़ीस। अब इन्हा पहली जईसे जंगल नी रहीगे। इहा अब खेत खार बारी बखरी बन गेहे।

देखने को भी नहीं मिलते अब घानी

डा. प्रकाश पतंगीवार

प्राचीन काल में जब मानव ने खाना पीना, फल फूल छोड़ कर अन्न खाने लगा, तब अनाज के साथ तेल उपजाना या तेल का महत्व समझा जाने लगा। पहले तिलहन को यूं खाता रहा। फिर तिलहन से तेल निकालना भी सीखा। प्राचीन काल में तेल निकालने के साधन को तिलही या तिरही कहा जाता था। इसका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया था। लकड़ी के दो मोटे लट्ठों का आधार लेकर प्रणालिका द्वारा कुचल दिया जाता था। तिलहन को मोहलाईन वृक्ष के तने की छाल से खूब रगड़ा जाता था। प्रणालिका से तेल निचुड़कर सतह पर रखे बर्तन में टपकने लगता था। तिरही से तेल निकालने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तिरही का उपयोग प्राचीन काल से मध्य काल तक सतत जारी रहा। मनुष्य के दैनिक जीवन में तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर तेल न होता, तो हमारे पकवान कैसे पकते। अच्छा हुआ जो मानव ने तिलहन को पहचाना और तेल के अलग अलग प्रयास किए। तब जमाना मशीन का नहीं होता था। जब मनुष्य का धैर्य टूट गया, पशु बल से काम लिया जाने लगा, इसे कोल्हू कहा गया। आंचलिक भाषा में इसे घानी बोला जाता है। घान यानी तादात, यह तिलहन डालने की गणना पर आधारित होता है। घानी में तिलहन डालने से वह स्पेलर (अलग अलग) कर देता है। तेल और खली अलग अलग हो जाते हैं। वर्तमान में कोल्हू गायब हो चुके हैं। पहले हर वि ख में कोल्हू या घानी वह भी बहुतायत में होते हैं। आज की स्थिति में उनके निशान भी नहीं मिलते हैं। घानी का तेल सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि तेल पेरते समय तापमान कम होता था। पोषक तत्व बना रहता था, तीक्ष्ण गंध होती थी, तीखा होता था।

वातानुकूलित होती पुलिस

टफ और सुपर कॉप टाइप की पुलिसिंग का अंत

एसी केबिन, एसी गाड़ियां और अब एसी हेलमेट भी

एसी जैसी सुविधाओं के लिए निर्धारित है गाइड लाइन

सिपाही से लेकर दरोगा तक के घर, दफ्तर, गाड़ियों मे है एसी

बिजली, पेट्रोल डीजल सरकार का और टैक्स जनता देगी

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 9424225829

काश छत्तीसगढ पुलिस रायपुर पुलिस कमिश्नरेट जैसे हिमायती अफसर हमारी आर्मी में भी होते। तपते रेगिस्तान और ठिठुरा देने वाली बर्फीली पहाडियों से लेकर खतरनाक जंगली सीमा में तैनात हमारे बहादुर फौजियों के लिए भी एसी, हिटर और आरामदायक संसाधन होते तो क्या बात थी। पहले से ही रायपुर पुलिस अब वातानुकूलित फोर्स कहलाती थी अब तो महज चंद घंटों में चालान काटने वाली ट्रैफिक पुलिस को दफ्तर, गाड़ियों के बाद एसी हैलमेट भी देने की तैयारी है। हार्ड वर्क, टफ जॉब और विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी इमानदारी से ड्यूटी के लिए वर्दीधारियों को मजबूत बनाया जाता था। लेकिन लगता है प्रशिक्षण के साथ चयन भी वातानुकूलित हो गया है। अरे साहब अगर इतनी ही चिंता है तो ड्यूटी टाइमिंग सुधार लीजिए इतनी गर्मी, सर्दी और बारिश तो कोई एनसीसी कैडेट भी झेल लेता है। तो ऐसा क्या तीर यातायात पुलिस ने मार लिया है कि उन्हें एसी हैलमेट देने की तैयारी में है आप सब! अब भी ट्रैफिक जाम, बेतरतीब पार्किंग और सड़क पर दुकानें आम राहगीरों के लिए परेशानी का सबब है उस पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ कैमरे से फोटो खिंचकर वसूली से सब बेजार है। महकमे के पास बहुत पैसा है तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते आप।

ट्रैफिक जवानों को प्रतिदिन कई घंटे खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर यातायात नियंत्रित करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में जवानों को एसी वाले हेलमेट देने की तैयारी चल रही है। रायपुर में शनिवार को उसका ट्रायल शुरू किया गया।

यह तकनीक न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ा सकती है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि ट्रायल सफल रहता है तो भविष्य में अधिक संख्या में ट्रैफिक जवानों को ऐसे हेलमेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पुलिस विभाग का मानना है कि बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने से जवानों की कार्यकुशलता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी।

विवेक शुक्ला, एडीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि एक कंपनी द्वारा कुछ एसी हेलमेट ट्रायल के लिए उपलब्ध कराए हैं। भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक जवानों को राहत देने के उद्देश्य से इनका परीक्षण किया जा रहा है।

8 से 15 डिग्री तापमान कम कर सकता है हेलमेट

हेलमेट के ऊपरी हिस्से में एक छोटा बैटरी संचालित फैन और एयर-डक्ट सिस्टम लगा होता है। पीछे कमर या बेल्ट पर बैटरी पैक लगाया जाता है, जो फैन बाहर की हवा को खींचकर फिल्टर करता है और चेहरे व सिर की ओर भेजता है। कुछ मॉडलों में कूलिंग मॉड्यूल भी होता है, जो हवा का तापमान कुछ डिग्री कम कर देता है। एक बार चार्ज होने पर यह सामान्यतः 6 से 8 घंटे तक काम करता है। कंपनियों के दावों और पुलिस ट्रायल रिपोर्टों के अनुसार यह सिर के आसपास के तापमान को लगभग 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम महसूस करा सकता है, जिससे हीट स्ट्रेस और लू का खतरा घटता है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27